वूमेन एक्सप्रेस

www.womenexpress.in

Email: thewomenexpress@gmail.com

Women Express tv

● वर्ष 9 ● अंक 136 ● हिन्दी दैनिक ● नई दिल्ली शुक्रवार 23 जुलाई 2021 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य 1 रूपया ● डाक पंजीयन DL (E)-20/5448/2017-19

हंगामा

संसद में केंद्रीय मंत्री के बयान के पन्ने फाड़े

घमासान बढ़ने पर संसद की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, बीजेपी सख्त

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। पेगासस फोन जासूसी विवाद और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ संसद में चल रहा विपक्ष का हंगामा अब घमासान में तब्दील हो गया है।

राज्यसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्यों ने तो संसदीय परंपरा की सीमा लांघते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से सदन में कागज छीनकर उसे फाड़ दिया और आसन की ओर उछाल दिया। माना जा रहा है कि इस अशोभनीय कृत्य के लिए टीएमसी सदस्य शांतनु सेन को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया जा सकता है।

राज्यसभा में तृणमूल सदस्यों का यह आक्रामक व्यवहार तब सामने आया जब दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई।

कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए वेल में आकर हंगामा कर रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य पेगासस फोन जासूसी कांड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुटे थे।

इस बीच उपसभापति हरिवंश ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पेगासस मामले में बयान देने की अनुमति दे दी। वैष्णव ने बयान पढ़ना अभी शुरू ही किया था कि टीएमसी सदस्य शांतनु सेन ने अचानक उनकी सीट के पास जाकर उनके हाथों से कागज छीन लिया और उसे फाड़कर आसन की ओर उछाल दिया।

टीएमसी सदस्य के इस आक्रामक रुख को देखकर भाजपा सदस्य भी उनकी ओर बढ़े तो डोला बनर्जी समेत टीएमसी के कुछ दूसरे सदस्य भी सेन के बचाव में आ गए। इस दौरान सदन में तनाव, गर्मागर्मी और टकराव की स्थिति

पैदा हो गई। टीएमसी सदस्यों की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी झड़प हुई। हरिवंश ने तृणमूल सदस्यों के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए अश्विनी वैष्णव को अपना बयान सदन के पटल पर रखने की अनुमति दे दी और इसके बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

सरकार के संसदीय रणनीतिकारों की बैठक में इस मामले को गंभीर मानते हुए संसदीय मर्यादा तोड़ने वाले विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मंत्रणा हुई। संकेत हैं कि सेन और बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ सदस्यों की ओर से सदन में प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

उधर, लोकसभा की कार्यवाही भी लगातार तीसरे दिन जासूसी कांड और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर नहीं चल पाई। कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना और अकाली दल से लेकर द्रमुक सरीखे अधिकांश विपक्षी दलों ने जंतरमंतर पर चल रही किसान संसद का समर्थन करते हुए वेल में आकर भारी हंगामा किया।

विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर संग्राम करने से पहले सुबह संसद परिसर में कृषि कानून विरोधियों के समर्थन में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुआई में पार्टी के दोनों सदनों के सदस्य कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग वाले पोस्टरबैनर लिए गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए और किसानों के समर्थन में मुखर आवाज उठाई।

संसद की मर्यादा के खिलाफ काम करने का टीएमसी का पुराना इतिहास रहा है। शोर मचाना, कागज फाड़ना उनकी संस्कृति है। सच्चाई यह है कि विपक्ष अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संसद की कार्यप्रणाली में अवरोध डालकर देश की विकास यात्रा को रोकना चाहता है। यह लोकतंत्र का अपमान है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख में क्षेत्रीय असमानता समाप्त करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इससे पूरे क्षेत्र के समग्र विकास को मिलेगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्च गुणवत्ता युक्त इस्पात क्षेत्र के लिए 6322 करोड़ रुपए के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिससे 40 हजार करोड़ का निवेश होने और 68 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार को मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस्पात क्षेत्र के लिए 6322 करोड़ रुपए का

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में उत्पादों के निर्माण के लिए यह राशि अगले पांच वर्ष में दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना से देश में 'हाई ग्रेड स्पेशियलिटी स्टील' के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना से लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और 25 टन की क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। योजना की अवधि 2023-24 से 2027 28 तक शुरू होकर पांच वर्ष होगी।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उत्पादन और निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में लगभग 5.25 लाख की रोजगार सृजन क्षमता है, जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष और शेष अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उच्चतम न्यायालय में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम के अस्तित्व में आने के चार साल बाद भी न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि अधिकरण की अनुपस्थिति में पीड़ित नागरिक संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश हैं और इससे उच्च न्यायालयों पर भी काम का बोझ बढ़ा है। अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है, ''अपील न्यायाधिकरण के न होने के कारण वादियों को उचित समय के भीतर न्याय नहीं मिल पाता है और इससे देश भर में वादियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है।'' याचिका में कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय और अन्य पीठों का गठन वक्त की मांग है और इसे अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता।

दैनिक भास्कर, भारत समाचार चैनल के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी

कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने छापेमारी का किया विरोध

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में दो प्रमुख मीडिया समूहों दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश के हिंदी समाचार चैनल भारत समाचार के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दैनिक भास्कर के मामले में भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और नोएडा समेत 30 स्थानों पर छापेमारी की गयी। छापेमारी सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुई और शाम तक जारी रही। दैनिक भास्कर समूह की मौजूदगी 12 राज्यों में हैं और यह ड्क्षहदी, गुजराती तथा मराठी में समाचारपत्रों का प्रकाशन करता है। यह सात राज्यों में 30 रेडियो केंद्रों का भी संचालन करता है और छह वेब पोर्टल तथा चार मोबाइल फोन ऐप के साथ इसकी ऑनलाइन उपस्थिति भी है। पहचान

जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए एक अधिकारी ने कहा, समूह कपड़ा और खनन व्यवसायों में भी शामिल है और विभाग इनके लेनदेन को भी देख रहा है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार के प्रवर्तकों और कर्मचारियों को निशाना बनाकर की गयी छापेमारी के संबंध में आयकर विभाग या उसके नीति निर्माण निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने इस कार्रवाई की ड्क्षनदा की। आयकर के छापों को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि एजेंसियां अपना काम करती हैं और इनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता।'' सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में संवाददाताओं के सवालों पर कहा, एजेंसियां अपना काम करती हैं और उन पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।'' दोनों मीडिया संगठन देश में कोविड19 प्रबंधन की आलोचना करते रहे थे और अप्रैलमई में देश को बुरी तरह प्रभावित करने वाली वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान इस विषय पर कई खबरें प्रकाशित / प्रसारित की थीं। तलाशी का ब्योरा देते हुए सूत्रों ने बताया कि लखनऊ में भारत समाचार और उसके प्रवर्तकों और कर्मचारियों के परिसरों पर छापेमारी की गई।

दिल्ली में 31 जुलाई तक सरकारी सेंटरों पर कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज लगेगी

नई दिल्ली । दिल्ली में 31 जुलाई तक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज़ ही लगाई जाएगी। कोविशील्ड के कम स्टॉक के कारण दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक मई से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 84 दिन का साइकिल पूरा होने के बाद अब आने वाले दिनों में इनमें से काफी लोग दूसरी डोज़ के पात्र हैं। दिल्ली को 21 जुलाई को केंद्र से मिली 70 हजार डोज कोवैक्सीन की सप्लाई दी गई। दिल्ली में अब एक

दिन से भी कम का वैक्सीन स्टॉक है। 2,45,590 डोज कोविशील्ड और 65,460 डोज को वैक्सीन उपलब्ध है। को वैक्सीन के स्टॉक से सिर्फ 20 फीसदी वैक्सीन ही पहली डोज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कम स्टॉक के कारण 31 जुलाई तक कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। 21 जुलाई को 63,406 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक कुल 95,18,884 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। दिल्ली के 313 सेंटरों की 560 साइटों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। यहां रोज 90,797 लोगों के वैक्सीनेशन की क्षमता है।

मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगे 70 पोर्न वीडियो

राज कुंद्रा ने बचने के लिए एक अफसर को दिए 25 लाख रुपए

(विशेष संवाददाता)

मुंबई । एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पार्नोग्राफी के मामले में फंसते जा रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि उसके हाथ आरोपी उमेश कामत की ओर से बनाए गए करीब 70 वीडियो लगे हैं। ये सभी वीडियो कामत ने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की मदद से बनाए थे।

उधर, पोर्न मूवी केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम राज कुंद्रा के मुंबई स्थित विआन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कम्प्यूटर्स की

हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज कर दिया। माना जा रहा है कि यहीं से वी ट्रांसफर के जरिए पोर्न वीडियो को अपलोड किया जाता था।

सूत्रों के मुताबिक हॉटशॉट ऐप पर अपलोड किए गए 20 मिनट से 30 मिनट तक के कुल 90 वीडियो भी क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा को ये वीडियो दिखाए गए जो उमेश कामत ने ब्रिटेन की प्रोडक्शन कंपनी केनरिन को भेजे थे। सूत्रों ने यहां तक कहा कि राज कुंद्रा का साथी और आईटी हेड रायन थोर्पे भी टूट गया और उसने जांच अधिकारियों को बताया कि इस पूरे रैकेट में उसका रोल कुंद्रा और अन्य स्टाफ को यह बताना था कि किस तरह से टेक्निकल चीजों से एहतियात बरतकर वो कानून से बच सकते हैं। राज कुंद्रा के दो ऑफिस विआन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एलजी स्ट्रीमिंग पर छापेमारी की गई। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फरार आरोपी के दावे ने अब पुलिस महकमे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पॉर्न फिल्म मामले में फरार आरोपी यश ठाकुर ने दावा किया है कि पुलिस पहले ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारी को 25 लाख रुपये घूस दिए हैं। यश ठाकुर का दावा है कि उनसे भी पुलिस ने रिश्वत मांगी थी।

पिछड़े जिलों में 130 मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र द्वारा प्रायोजित 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (आरयूएसए) योजना के तहत 130 मॉडल डिग्री कॉलेज देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में खोले जाने की मंजूरी दी गई है।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा को यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने 374 पिछड़े जिलों की पहचान की है जहां 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा में सकल भर्ती अनुपात (जीईआर) 12.4 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से कम है। प्रधान ने बताया ''शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में मॉडल डिग्री कालेज खोलने की पूर्ववर्ती योजना के तहत यूजीसी ने 64 मॉडल डिग्री कॉलेजों को सहायता की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा ''पूर्ववर्ती योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) योजना में मिला दिया गया है। आरयूएसए ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 130 मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। आरयूएसए योजना के तहत सबसे अधिक 26 मॉडल डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं जबकि ओडिशा के लिए 14 और छत्तीसगढ़ के लिए 10 मॉडल डिग्री कालेजों को मंजूरी दी गई है।

प्रदर्शन खत्म करके वार्ता के लिए आएं तोमर की प्रदर्शनकारी किसानों से अपील

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । तीन नये कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए कुछ किसानों के जंतरमंतर पर पहुंचने के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर ने बृहस्पतिवार को उनसे आंदोलन का रास्ता छोडक़र वार्ता के लिए आने की अपील की। तोमर ने दावा किया कि देशभर में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से विशेष अनुमति मिलने के बाद 200 किसानों का एक समूह संसद के मानसून सत्र के बीच केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में मध्य दिल्ली में संसद भवन परिसर के समीप जंतर मंतर पहुंचा। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच नौ अगस्त तक प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। जंतरमंतर पर किसानों के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा, '' मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों को विरोध का रास्ता

छोडक़र वार्ता के लिए आना चाहिए। यदि वे विधेयकों में किन्हीं मुद्दों को लेकर आते हैं तो हम उन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यदि वे अपने प्रस्ताव के साथ आते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और पिछले सात सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई अहम कदम उठाये गये हैं जिनके फायदे देशभर में किसानों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा,'' तीनों कृषि विधेयक इस दिशा में एक कदम हैं। देशभर में किसानों ने इन विधेयकों का समर्थन किया है। तोमर ने बुधवार को लोकसभा में लिखित जवाब में यह दोहराया था कि सरकार पिछले साल संसद से पारित हुए तीनों कृषि कानूनों को लेकर मुद्दों के समाधान के लिए प्रदर्शनकारी कृषक संगठनों के साथ चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा, '' सरकार मुद्दों के समाधान के लिए कृषक संगठनों के साथ गंभीर, संवेदनशील एवं सक्रिय चर्चा में शामिल रही है।

संसद के करीब शुरू हुई किसान संसद

कृषि बिलों के विरोध में जंतर मंतर पर शुरू हुआ किसानों का आंदोलन

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । पिछले आठ महीनों से भीषण सर्दीगर्मी और बरसात झेल रहे प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर बृहस्पतिवार को जंतरमंतर पहुंचे। यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित संसद में मानसून सत्र चल रहा है। किसानों ने यहां तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।

भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के हरपाल सिह ने अपना भगवा साफा बांधते हुए कहा, हम कई अपनों को खोने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम तैयारी से आये हैं।'' पुलिस की सुरक्षा के साथ 200 किसानों का एक समूह चार बसों से सिघू बॉर्डर से जंतरमंतर पहुंचा। किसान यहां अपनी पहचान उजागर

करने वाले बैज पहनने के साथसाथ हाथ में अपनी यूनियनों के झंडे लिए हुए नजर आए। प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होना था, लेकिन किसान यहां 12 बजकर 25 मिनट पर पहुंचे। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि रास्ते में पुलिस ने उन्हें तीन जगह रोका और उनके आधार कार्ड देखे। हरपाल सिह ने कहा, पाकिस्तान से आने वाली बस को भी ऐसी कड़ी तलाशी से नहीं गुजरना पड़ता है... सरकार किसानों को परेशान करना चाहती है।'' उन्होंने कहा, हमारी दो बसें रास्ते में ही खराब हो गयीं और तब पुलिस डीटीसी बसों में लेकर आयी।'' जंतर मंतर पर पहुंचने पर किसानों ने हवा में मुक्के लहराते हुए नारेबाजी की और सरकार से तीनों कानून रद्द करने की मांग की। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों को जंतरमंतर के एक छोटे से हिस्से में सीमित कर दिया गया और पुलिस ने दोनों ओर अवरोधक लगा रखे हैं। ओड़िशा, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए। पहले दिन उन्होंने किसान संसद का आयोजन भी किया जिनमें दो सत्रों में एपीएमसी अधिनियम में बदलावों पर चर्चा हुई। बीच में भोजनावकाश के दौरान लंगर की भी व्यवस्था थी। बहस में महिलाओं एवं बुजुर्गों का भी मुद्दा उठा। तीनों कानूनों का विरोध कर रहे किसानों संगठनों के संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बताया कि केरल के 20 सांसद किसान संसद में पहुंचे और उन्होंने उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित की।

उसने कहा कि किसी भी नेता को मंच साझा नहीं करने दिया गया , इसलिए ये सांसद दर्शक के रूप में शामिल हुए। किसान नेताओं ने कहा कि 13 अगस्त तक रोजाना 200 किसान तीनों कानूनों पर हर उपबंध पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर आयेंगे। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की आवजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पेगासस जासूसी संबंधी खबरों को भाजपा ने बताया मनगढंत

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का दावा, सबकुछ है काल्पनिक, मानहानि को दावत देने वाली

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 22 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां फिर दावा किया कि कथित इजराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिये भारतीयों की कथित जासूसी संबंधी कहानी मनगढंत, काल्पनिक और बगैर साक्ष्य के है और इस पर अधारित खबरें मानहानि को दावत देने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेगासस परियोजना से संबंधित मानवाधिकार समूहों ने कथित जासूसी के संभावित निशानों की सूची होने से इंकार किया है। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी सूची यहां वहां से संग्रह किए गए मोबाइल नंबरों पर आधारित है, उनका इस्तेमाल पीत पत्रकारिता के लिए किया जा रहा है।

वह उन खबरों का जिक्र कर रही थी जिनमें कथित तौर पर कुछ राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों सहित अनेक भारतीयों की निगरानी संबंधी खबरें छपी हैं। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पेगासस प्रोजेक्ट के नतीजों के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा है और आंकड़े अकाट्य रूप से एनएसओ ग्रुप के पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के संभावित लक्ष्यों के साथ जुड़े हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह टिप्पणियां तब आयी हैं जब मीडिया में आयी कुछ खबरों में कुछ इजराइली पत्रकारों के हवाले से कहा गया है कि मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि उसने यह कभी नहीं कहा कि हाल में लीक हुए फोन नंबर खासतौर से उन नंबरों की सूची में थे, जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। लेखी ने पत्रकारों से कहा कि 10 देशों के नाम सामने आए हैं जहां इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ।

उन्होंने कहा कि इन देशों के विपक्षी दलों ने वैसा रवैया नहीं अपनाया जैसा भारत में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल अपना रहे हैं। ज्ञात हो कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल मानसून सत्र के पहले दिन से हंगामा कर रहे हैं और संसद की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

गौरतलब है कि मीडिया संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ने दावा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कुछ रसूखदार लोगों सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर, हो सकता है कि हैक किए गए हों।

लेखी ने दावा किया, यह कोई खबर नहीं है। क्योंकि यह मनगढंत, काल्पनिक और साक्ष्यों से परे है। ऐसी खबरें फर्जी और मानहानि को दावत देने वाली है। उन्होंने कहा, छपी हुई खबरें उन नंबरों की सूची पर आधारित हैं जो किसी भी डायरेक्ट्री (निर्देशिका) में उपलब्ध हों। एमनेस्टी ने भी इस सूची से इंकार किया है और कहा है कि इससे उनका कोई लेनादेना नहीं है। पेगासस सॉफ्वेयर बनाने वानी कंपनी एनएसओ ने भी कहा कि ये दावे अपुष्ट हैं और उसके ग्राहक संबंधी आंकड़ों से मेल नहीं खाते। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि पेगासस विवाद का संबंध उस संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है जिसकी वह अध्यक्ष रह चुकी है और जिसने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की समीक्षा की थी।

उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है और उसे संसद की मंजूरी दी जाने वाली है। डेटा संरक्षण देश में कानून बनने जा रहा है। यह मामला इसी से जुड़ा है। भारत को संस्थागत तरीके से कमजोर करने की यह साजिश है। यह भारत के मान व सम्मान को गिराने की साजिश है।

एक नजर

ट्विटर अपवोट और डाउनवोट बटन की कर रहा है टेस्टिंग

नई दिल्ली, 22 जुलाई । ट्विटर अब एक ऐसे नए फीचर का टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स ट्वीट पर दिए गए उत्तरों को अपवोट और डाउनवोट करने में सक्षम होंगे। ट्विटर ने कहा है कि यह अभी भी डिसलाइक बटन नहीं है। वर्तमान में आईओएस यूजर्स के एक चुनिंदा समूह के साथ टेस्टिंग के तहत, यह सुविधा विभिन्न शैलियों (ऊपर और नीचे तीर, एक दिल आइकन और एक नीचे तीर, और अंगूठे ऊपर और नीचे के चिह्न) में उपलब्ध है। ट्वीटर ने गुरुवार को जो पोस्ट किया उनमें कहा गया है, आईओएस पर आप में से कुछ लोगों को उत्तरों पर वोट अप या डाउन वोट करने के लिए अलगअलग विकल्प दिखाई दे सकते हैं। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि आप एक कॉन्वो में प्रासंगिक उत्तरों के प्रकारों को समझें, इसलिए हम उनमें से अधिक दिखाने के तरीकों पर काम कर सकते हैं। कंपनी ने सूचित किया कि, आपके डाउनवोट सार्वजनिक नहीं हैं, जबकि आपके अपवोट को लाइक के रूप में दिखाया जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अनुसार, प्रयोग अभी शोध के लिए एक टेस्टिंग है ।

निगमायुक्त ने किया शास्त्री पार्क का दौरा, खुले में पड़ा मलबा उठाने के दिये निर्देश

नई दिल्ली, 22 जुलाई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त विकास आनंद ने आज शास्त्री पार्क क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें शास्त्री पार्क समुदाय भवन के पास खुले में मलबा पड़ा मिला। निगमायुक्त विकास आनंद ने तुरंत संबंधित निगम अधिकारियों और मेट्रो वेस्ट कंपनी को निर्देश दिये कि वे तुरंत प्रभाव से खुले में पड़े हुए मलबे को उठवाकर क्षेत्र को साफ करवायें। निगमायुक्त के आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा जेसीबी मशीनें लगवाकर तुरंत मौके से मलबा उठवा दिया गया। अधिकारियों ने निगमायुक्त को बताया कि शास्त्री पार्क समुदाय भवन के पास स्थित खाली जमीन डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आती है जहां पर खुले में मलबा पड़ा है। निगमायुक्त के निर्देशानुसार इस संबंध में डीडीए को चालान जारी किया गया है। विकास आनंद ने क्षेत्र का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपरोक्त खाली भूमि में जगह जगह हुए जलभराव में एंटी लारवल दवा का छिड़काव करवायें जिससे मच्छर ना पनप सकें।

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की दो दिवसीय ब्रिटेन यात्रा आज से

नई दिल्ली, 22 जुलाई । विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की दो दिवसीय ब्रिटेन यात्रा शुक्रवार से शुरू होगी। इस दौरान वह ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ मई में जारी 10 वर्षीय रोपडमैप के क्रियान्वयन सहित द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि श्रृंगला ब्रिटेन के अपने समकक्ष के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच एक डिजिटल शिखर सम्मेलन में 'रोडमैप 2030' स्वीकार किया गया था, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक समग्र रणनीतिक भागीदारी तक ले जाने पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''यात्रा के दौरान, विदेश सचिव अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और रोडमैप 2030 के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा करेंगे।' उन्होंने कहा, ''वह पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

विवाद समाधान का महत्वपूर्ण तंत्र है मध्यस्थता: सीजेआई

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि ब्रिटिश लोगों और उनकी अदालत प्रणाली के आने से पहले भारत में आम तौर पर की जाती रही मध्यस्थता आज विवाद समाधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है तथा भविष्य में भी इसकी उपयोगिता बढ़ती रहेगी।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लोगों ने न सिर्फ आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की स्थापना की, बल्कि यह मिथक भी गढ़ा कि विवाद समाधान और न्याय के लिए काले कोट और गाउन पहनना तथा दलीलें प्रस्तुत करना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ''यह समय इस तरह के मिथकों और मतों को खत्म करने का है। सत्य यह है कि भारत में ज्यादातर वादियों को अनेक तरह की सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विवाद समाधान के त्वरित,

किफायती और सुविधाजनक तरीके चाहिए। उन्होंने कहा, ''मध्यस्थता किसी विवाद से जुड़े पक्षों के लिए उपलब्ध एक ऐसा तंत्र है जिसमें उपर्युक्त विशेषताएं हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त कि पक्षों के लिए यह किफायती, समय बचाने वाली और सुविधाजनक विधि है, मध्यस्थता का दूसरा आयाम यह है कि शायद पक्षों के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। प्रधान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय से प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल वर्चुअल मीडिएशन समर स्कूल, 2021' में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता आज विवाद समाधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है तथा भविष्य में भी इसकी उपयोगिता बढ़ती रहेगी।

मनजीत सिंह जीके ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सीबीआई जांच की मांग

मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के हरपाल थापर की जेल में हुई मौत की निष्पक्ष जांच जरूरी

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली 22 जुलाई । जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनाथ आश्रम संचालक हरपाल सिंह थापर की घाघीडीह जेल में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।

जीके ने लिखा है कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक हरपाल सिंह थापर को झूठे आरोपों में जेल भेजने के बाद, घाघीडीह जेल में टार्चर करने तथा उसके बाद जेल में समुचित इलाज ना मिलने के कारण मौत हो गई है।

थापर के परिजनों ने जेल में पिटाई का भी आरोप लगाया है। टेल्को घोड़ाबांधा स्थित शमशेर टावर में थापर और उनकी पत्नी अनाथ बच्चों के लिए ट्रस्ट का संचालन करते थे,

जिसमें करीब 40 बच्चे रहते थे। इनका पालन पोषण थापर अपने आर्थिक स्त्रोतों से करके समाज की बड़ी सेवा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं की इस जमीन पर नजर थी, जिस वजह से साजिश करके थापर को यौन शौषण के फर्जी आरोपों में जेल भेजने का परिवार दावा कर रहा है। चूंकि हरपाल सिंह थापर मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक थे, जिसकी काफी संपत्ति बताई जा रही है।

इनके अनाथ आश्रम में लावारिस बच्चों को रखा जाता था। थापर और उनकी पत्नी पुष्पा तिर्की सहित चार लोगों को 15 जून को पुलिस ने ट्रस्ट के नाबालिगों से अश्लील हरकत सहित अन्य आरोपों में मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था। उसके बाद 17 जून से ही वो जेल में थे।

जीके ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री सोरेन से मांग की है कि थापर के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए तुरंत झारखंड सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। साथ ही थापर की पत्नी तथा अन्य लोगों को तुरंत जेल से रिहा करके उनके अनाथ आश्रम को फिर से शुरू किया जाए और प्राकृतिक न्याय के नियमों के यह अनुरूप होगा कि मामले की जांच पूरी होने तक आरोपी पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सेवा से निलंबित किया जाए।

14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत शिक्षण पद रिक्त

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । सरकार ने बृहस्पतिवार को स्वीकार किया कि देश के कम से कम 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं तथा इनमें से दो संस्थानों में 70 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष एक अप्रैल तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 33.4 प्रतिशत शिक्षण पद और 37.7 प्रतिशत गैर शिक्षण पद रिक्त पड़े थे। प्रधान ने यह भी कहा, '' रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। तीन वर्ष से अधिक रिक्त पड़े पदों के बारे में केंद्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 45 विश्वविद्यालयों में 19,911 स्वीकृत शिक्षण पद हैं जिनमें से छह हजार पद रिक्त पड़े हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिक्षण पद दिल्ली विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े हैं।

इस विश्वविद्यालय में स्वीकृत शिक्षण पद 1,706 हैं जिनमें से 846 रिक्त हैं। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नंबर आता है जहां 863 स्वीकृत शिक्षण पदों में से 598 पद रिक्त हैं।

इन आंकड़ों से यह बात भी सामने आयी 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक यानी 23 में 30 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं जबकि मात्र तीन विश्वविद्यालयों में 20 प्रतिशत से कम रिक्तियां हैं।

अदालत ने ऑटो, टैक्सी चालकों के लिए वर्दी के खिलाफ याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

(लोकेश निरवाल)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के अनिवार्य रूप से वर्दी पहनने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिह की पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया। दरअसल, याचिका में कहा गया है कि वर्दी नहीं पहनने पर राष्ट्रीय राजधानी में चालकों को 20,000 रुपये तक का चालान जारी किया जा रहा है, जबकि इस विषय पर कानून अस्पष्ट है।

चालकों के यूनियन 'चालक शक्ति' ने यह याचिका दायर की है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक और एक टैक्सी चालक ने आरोप लगाया है कि वर्दी के जरिए चालकों को एक अलग पहचान प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14,19(1) (जी) और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक

अधिकारों का हनन करता है।

याचिका में कहा गया है कि वर्दी उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी डालता है जिससे वे स्वच्छता पर कम खर्च कर पाते हैं और इससे यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। यूनियन और चालकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पारस जैन ने अदालत से कहा कि वर्दी के रंग पर प्राधिकारों के बीच एक राय नहीं है।

दिल्ली मोटर वाहन नियम,1993 का नियम7 खाकी रंग का प्रावधान करता है जबकि राज्य प्राधिकारों के अनुसार यह स्लेटी रंग का होना चाहिए। अदालत ने विषय की सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त तय की है।

दिल्ली दंगा की आरोपी नरवाल को पीएचडी के लिए अस्थायी पंजीकरण की अनुमति मिली

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि छात्रा नताशा नरवाल को पीएचडी कार्यक्रम के लिए अस्थायी पंजीकरण दिया गया है। नरवाल पिछले साल उत्तरपूर्वी दिल्ली ड्क्षहसा से संबंधित मामलों में आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान को विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया कि प्राधिकारों द्वारा नरवाल को जारी नोटिस के कारण लंबित कार्यवाही के दौरान भी उनके पंजीकरण के अनुसार वह अस्थायी पंजीकरण के सभी लाभों की हकदार होंगी। अदालत ने जेएनयू की तरफ से पेश अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा के बयान को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और याचिका का निपटारा कर दिया। अधिवक्ता अरोड़ा ने कहा कि 'पिजरा तोड़' मुहिम की कार्यकर्ता नरवाल को मॉनसून सेमेस्टर 2020 और शीतकालीन सेमेस्टर 2021 के पीएचडी कार्यक्रम में अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है। अदालत पीएचडी कार्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर में अस्थायी रूप से पंजीकरण करने की अनुमति का अनुरोध करने वाली नरवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नरवाल ने विश्वविद्यालय को अस्थायी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लॉगिन आईडी और पहचान पत्र प्रदान करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

उत्तर प्रदेश के पांच जिलों से होकर गुजरेगा चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग

एनएच 27 और एनएच 28 के तमाम शहर शामिल होंगे

(शरद पाण्डेय/वूमेन एक्सप्रेस)

नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे में शामिल करने के बाद अयोध्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश के पांच जिलों से होकर गुजरेगा।

यह मार्ग इन पांच जिलों के अलावा आसपास के अन्य जिलों के लिए वरदान साबित होगा। 275 किमी। लंबा यह मार्ग फैजाबाद,अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती जिलों से होकर गुजरेगा।

चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पांच जिलों के 107 गांवों के आसपास से गुजरेगा। इस मार्ग का डिजाइन पीक आवर में आने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे भविष्य में ट्रैफिक जाम की समस्या न हो।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के बीचोबीच से 8 से 30 मीटर की खाली जगह यानी आरओडब्ल्यू (राइट आफ वे) उपलब्धता के अनुसार छोड़ी जाएगी।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं ट्वीट कर प्रोजेक्ट को हाईवे में शामिल करने की जारकारी दी है।

इन शहरों से गुजरेगा प्रोजेक्ट

सड़क परिवहन मंत्रालय ने चौरासी कोसी परक्रिमा मार्ग को हाईवे शामिल किया

यह पांचों जिलों के तमाम शहरों से होकर गुजरेगा। छावनी (एनएच 27 के पास) आश्रम महबूबगंज (सूर्यकुंड) अमोराकटरिया श्रृंगी ऋषि गोसाईगंजतरुणरामपुर भगन द्राबगंज (सीताकुंड)बीकापुर भगवती नगर रेवतीगंज अस्थाना अधियोना चौराहा सिरसीर (जनमे) जयकुंड अमरगंज अमनीगंजरुदाली रोजागां व मियां का पुरबामेरामानपत्रंगा बरेनबाग कामियार अलीयाबाद नियामतगंज भोरीगंज राजापुर बाबा उमरी चारसारी सुभीरन दास कुट्टी नरहरदास की कुट्टी (पस्का) बेगमगंजदीकसीरपकरी बार गोहानीजारही चरहाराम नगर चौराहा (तुलसीपुर) नबाबगंजनबवा कल्याणपुर हैदराबाद बेरकानदुला रामगढ़छवानी (एनएच28 पर)। महबूब गंज गोसाईगंजइनायत नगर मिया का पुरवापतरंगाअलियाबाद नियामत गंज बारिन बागमुर्तियां घाट देवी गंजपस्का किनौना चौराहा राम गढ़ दीकिर राम नगर नवाब गंज बर्टा चौराहाछवानी (एनएच27) कटारिया।

24 ब्रिज और 217 पुलिया बनेंगी

चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में 241 छोटे बड़े ब्रिज और पुलिया बनेंगे। इनमें 3 बड़े और 21 छोटे ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 217 पुलिया भी बनाई जाएंगी।

महिला हेल्पलाईन न.

डीएमआरसी—155370
सीआईएसएफ—22185555
दिल्ली पुलिस—1091
दिल्ली सरकार—181
कहीं भी—कभी भी—1090

समाचार एजेंसी वेब वार्ता®
पल-पल की खबर हर पल
समाचार एजेंसी का सदस्य बनने के लिए संपर्क करें
9650061234

एक नजर

ईडीएमसी ने शुरू की पौधारोपण अभियान 'अडोप्ट ए ट्री' की शुरुआत

नई दिल्ली, 22 जुलाई। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने गुरुवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के पौधारोपण अभियान 'अडोप्ट ए ट्री' का गाजीपुर में कला निकेतन स्कूल के परिधि रोड़ पर पौधारोपण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थायी समिति बीर सिंह पंवार, पूर्व उपमहापौर संजय गोयल, उद्यान निदेशक राघवेंद्र सिंह और वरिष्ठ निगम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद, सुश्री अपर्णा गोयल ने की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इस अभियान के तहत 4880 पौधों को नागरिक गोद ले सकते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इन पौधों के लिए ट्री गार्ड भी उपलब्ध करा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा ही पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदने व ट्री गार्ड लगाने का काम किया जाएगा। 'अडोप्ट ए ट्री' अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली के सभी 64 वार्डों में पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। 'अडोप्ट ए ट्री' अभियान के तहत सड़क किनारे पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा फलदायी पौधे आम, जामुन, कदंब, आंवला, छायादार वृक्ष जैसे पीपल, बरगद आदि, औपधीय पौधे जैसे नीम, अर्जुन आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अंबेडकर अस्पताल में दो कर्मचारी 25 फुट गहरे गढ्ढे में गिरे, एक की मौत

नई दिल्ली, 22 जुलाई। दक्षिणपुरी इलाके में स्थित अंबेडकर अस्पताल में सीढ़ियों पर ग्रिल न होने के कारण अस्पताल के दो कर्मचारी 25 फुट गहरे गढ्ढे में गिरे गए। हादसे में नर्सिंग स्टाफ अमर सिंह की मौत हो गई। वहीं, सुरक्षाकर्मी दीपक मेहरा घायल हो गए। लापरवाही से हुई मौत के मामले में अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को मंगलवार शाम अंबेडकर अस्पताल में हादसे की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि अस्पताल के पिछले हिस्से में बने बेसमेंट में निर्माण कार्य चल रहा है। नर्सिंग स्टाफ अमर सिंह किसी काम से यहां आए थे। इस दौरान सीढ़ियों से फिसलकर वह गड्ढे में गिर गए। उन्हें बचाने के दौरान सुरक्षाकर्मी दीपक मेहरा भी गड्ढे में गिर गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने अमर सिंह को मृत घोषित कर दिया। दीपक मेहरा का इलाज चल रहा है। घायल दीपक मेहरा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचे तो गड्ढे से बचाओबचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो अमर सिंह गिरे हुए थे। दीपक उन्हें बचाने के लिए सरिया के सहारे गढ्ढे में उतरने लगे, लेकिन सरिया से हाथ कट जाने के कारण वह भी गढ्ढे में गिर गए। बाद में वहां पहुंचे अन्य लोगों ने दोनों को निकाल अस्पताल पहुंचाया। माना जा रहा है कि जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा सुरक्षा संबंधी पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बुराड़ी में किया राशन दुकानों का औचक निरीक्षण

राशन की दुकानों से प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी को ई-पीओएस के माध्यम से दिल्ली में राशन वितरण शुरू कर दिया

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 22 जुलाई। दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जुलाई के लिए मुफ्त राशन के सुचारू वितरण की जांच के लिए बुराड़ी में स्थित राशन की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे में बुराड़ी के विधायक, संजीव झा, सहायक आयुक्त (एफ एंड एस), खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी और प्रवर्तन दल के अधिकारी मंत्री जी के साथ मौजूद रहे। इमरान हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सभी राशन की दुकानों से प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी को ईपीओएस के माध्यम से दिल्ली में राशन वितरण शुरू कर दिया है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ईपॉस डिवाइस के सिस्टम को समझा और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। इमरान हुसैन ने एफपीएस दुकानों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से राशन के वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो। उन्होंने इस दौरान राशन की दुकानों (एफपीएस) द्वारा ई पीओएस डिवाइस के माध्यम से राशन वितरण सुचारू रूप से पाया। माननीय मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन वितरण से जुडी हेल्पलाइन नंबर 1967 और बीईएल द्वारा ई पीओएस

डिवाइस की तकनीकी सहायता के लिए 1800110841 की जानकारी भी प्रत्येक एफपीएस दुकान पर प्रदर्शित की जाए। इमरान हुसैन ने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि पीडीएस लाभार्थी को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा उन्हें तकनीकी कारण बताकर राशन से वंचित न किया जाए।

दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं।

वहीँ एएवाई श्रेणी के तहत नियमित पात्रता प्रति परिवार 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चीनी है। आम दिनों में योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से लाभार्थियों को दिया जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने लोगों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है।

इसके अलावा, प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई 2021 के लिए 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल सहित प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न का हकदार है। इस प्रकार पीआर और पीआरएस श्रेणी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह कुल 10 किलो खाद्यान्न यानी 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है। वहीँ प्रत्येक एएवाई परिवार को प्रति माह 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल के अलावा, एएवाई परिवार के प्रति सदस्य को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति माह मुफ्त मिल रहा है।

इमरान हुसैन ने आगाह किया कि राशन लाभार्थियों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें प्रदान किए जा रहे खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। सतर्कता समिति के सदस्य भी सक्रिय रूप से वितरण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों, सर्किल एफएसओ/एफएसआई को वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी पोर्टेबिलिटी पर दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ई पीओएस/ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के मार्गदर्शन में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्यान का वितरण अब दिल्ली में सभी ईपीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

सीबीएसई की 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। दिल्ली उच्च न्यायालय से एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस साल 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मूल्यांकन नीति में छात्रों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एनजीओ, जस्टिस फॉर ऑल ने दलील दी कि सीबीएसई को स्कूलों द्वारा अंक देने के लिए अपनाई जाने वाली योजना की 'सॉफ्ट कॉपी' अपलोड करने की व्यवस्था करनी चाहिए। एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता खगेश झा ने एक याचिका दायर कर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 10 वीं कक्षा के छात्रों के अंकों की गणना पर चिंता प्रकट करते हुए यह याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा कि इस साल स्कूल अंक देने की अपनी खुद की नीति रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी

छात्र के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं है कि उसे किस तरह से अंक प्रदान किया गया है और इसलिए पिछले साल की तरह ही छात्रों को उन दस्तावेजों तक पहुंच होनी चाहिए जिनके आधार पर मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने दलील दी, ''मेरे पास कोई मार्किंग (अंक देने की) योजना नहीं है। मेरे पास कोई नीतिगत दस्तावेज या मूल्यांकन का कागज नहीं है। इससे पहले एक प्रणाली होती थी और एक प्रक्रिया हुआ करती थी।

अधिवक्ता ने कहा कि किसी नीति या रिकॉर्ड के अभाव में कोई छात्र किसी शिकायत के निवारण के लिए उच्च न्यायालय नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे जान सकूं कि यदि मैंने 19 अंक पाए हैं, तो क्या यह मानवीय भूल है या स्कूल की कुछ मनमानी नीति है। उन्होंने 10 वीं कक्षा के छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना के लिए एक कारक के तौर पर स्कूल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किये जाने पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, ''यदि पिछले साल 30 प्रतिशत छात्र अनुतीर्ण रहे थे तो परीक्षा में बैठे बगैर इस साल भी 30 प्रतिशत छात्र अनुतीर्ण होने वाले हैं।

सीसीआई ने आमेजन को कारण बताओ नोटिस भेजा

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। आमेजन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे फ्यूचर ग्रुप द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से कारण बताओ नोटिस मिला है।

दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। देश की सबसे बड़ी खुदरा कंपनियों में से एक फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ रिटेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिग संपत्तियों के लिए 24,713 करोड़ रुपये का सौदा करने के बाद से उसके और अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी के बीच तेज कानूनी लड़ाई छिड़ी हुई है। आमेजन के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमें मौजूदा विवाद के तहत फ्यूचर द्वारा दायर शिकायत के आधार पर सीसीआई से कारण बताओ नोटिस मिला है।

हम भारत के कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मामले में सीसीआई के साथ पूरा सहयोग करेंगे।' प्रवक्ता ने साथ ही विश्वास जताया कि कंपनी सीसीआई

की चिंताओं को दूर करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा, 'चूंकि फ्यूचर के साथ हमारा कानूनी विवाद चल रहा है, और हम गोपनीयता के दायित्वों से भी बंधे हैं, हम इस समय किसी भी आरोप के गुणदोष या आधार पर टिप्पणी नहीं कर सकते।' सीसीआई और फ्यूचर ग्रुप से तत्काल कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं हुई।

फ्यूचर ग्रुप ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को सीसीआई के कारण बताओ नोटिस की एक प्रति सौंपी। उचतम न्यायालय मौजूदा विवाद को लेकर आमेजन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदों के लिए सीसीआई से मंजूरी लेने की जरूरत होती है। निगरानी संस्था के पास व्यापक शक्तियां हैं। इनके तहत, किसी भी समय यह पाए जाने पर कि अधिग्रहण करने वाली कंपनी ने गलत जानकारी दी है, सीसीआई लेनदेन के लिए दी गयी अपनी मंजूरी को रद्द कर सकता है।

सीसीआई ने चार जून को आमेजन को नोटिस भेजा था। सीसीआई ने अपने नोटिस में आमेजन पर फ्यूयर ग्रुप को लेकर अपनी रणनीतिक हित को छिपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि आयोग के सामने पूर्व में इस हित का खुलासा नहीं किया गया था। अगस्त 2019 में आमेजन फ्यूचर ग्रुप की असूचीबद्ध कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिडेट में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई थी।

समझौते के तहत उसे तीन से 10 वर्षों के बाद फ्यूचर रिटेल को खरीदने का अधिकार भी मिलता। लेकिन एक साल बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के साथ उसके रिटेल, थोक व्यापार, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिग व्यापार के अधिग्रहण के लिए 24,713 करोड़ रुपए का सौदा कर लिया। इसके बाद आमेजन फ्यूचर ग्रुप को सिगापुर अंतरराष्ट्रीय पंच निर्णय केंद्र (एसएआईसी) में ले गयी। पिछले साल अक्तूबर में सिगापुर पंचनिर्णय केंद्र के आपातकालीन पंच (ईए) ने अपने फैसले में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे पर आगे बढ़ने पर रोक लगा दिया।

डीयू दाखिला के लिए ओबीसी वर्ग के छात्रों को प्रमाणपत्र में तीन साल की छूट देने की मांग

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेबवार्ता)। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने ओबीसी छात्रों के जाति प्रमाण पत्रों को तीन साल की छूट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने डीयू के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी व डीन ऑफ कॉलेजिज डॉ. बलिराम पाणी से इस संबंध में मांग की है।

डॉ. सुमन ने कहा कि डीयू से संबद्ध कॉलेजों और विभागों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्सों में दाखिला लेने वाले ओबीसी छात्रों को प्रमाण पत्रों में छूट दी जाए। उनका कहना है कि जिन ओबीसी कोटे के छात्रों ने वर्ष 2019 में अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे उन्हें स्वीकार करते हुए दाखिला दिया जाए। ज्ञात हो कि कोविड19 से उपजी स्थिति को देखते हुए डीयू प्रशासन ने स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा के दाखिला के लिए प्रमाणपत्रों के लिए एक वर्ष की छूट दी है। डॉ. सुमन का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से एसडीएम कार्यालय व तहसील कार्यालय में कोविड के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, न ही जाति प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण हो रहा है। इसलिए जिनके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है उसे स्वीकार करते हुए उन्हें दाखिला दिया जाए ताकि छात्रों का साल बर्बाद न हो। उन्होंने बताया है कि जाति प्रमाण पत्रों की जांच ऑनलाइन नहीं की जाती बल्कि फिजिकली होती है। ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। डॉ. सुमन ने यह भी बताया है कि यूजी व पीजी कोर्सेज के लिए डीयू ने आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है।

अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी सिंचाई विभाग की जमीन

(नीरज पांडेय/वूमेन एक्सप्रेस)

नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह के निर्देशन पर दिल्ली स्थित मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग के हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला द्वारा अभियान चलाकर 5.21 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, उसके अलावा सिंचाई विभाग के अन्य जमीनों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। सिंचाई विभाग ओखला संगठन के अधिशासी अभियन्ता वी0के0 सिंह ने बताया कि मदनपुर खादर में 22.07.21 की सुबह 04 बजे कार्यवाही करके सिंचाई विभाग की भूमि पर रोहिंग्या कैम्पों को हटाते हुए तमाम अवैध निर्माण हटाये गये जो दिल्ली के मदनपुर खादर में स्थित थे, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.1080 हेक्टेअर है, इसकी कीमत 97 करोड़ रूपये है। अधिशासी अभियंता ने

बताया कि इस भूमि से सटी जकात फाउडेशन की भूमि पर पहले रोहिंग्याओं की बस्ती बसी हुई थी। इन लोगों ने सिंचाई विभाग की खाली करायी गयी भूमि पर भी स्थायी/अस्थायी कब्जा कर लिया था जिसे मुख्यमंत्री एवं जलशक्ति मंत्री के आदेश के बाद हटाया गया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के साथ 20 जुलाई, 2021 को बैठक करके इस जमीन को खाली कराये जाने का निर्णय लिया। तथा 22 जुलाई, 2021 को प्रातः उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस की मदद से ग्राम मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग की विभागीय भूमि खसरा नं0 612 को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। इस कार्यवाही के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों में सहायक अभियंता धीरज कुमार प्रथम, जिलेदार शशिभान सिंह के अलावा अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित थे।

कोविड से मरने वाले होटल भागीदारों के परिवारों की मदद के लिए ओयो ने पहल शुरू की

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेबवार्ता)। हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो ने कोविड19 महामारी का शिकार बनने वाले अपने होटल भागीदारों और घर मालिकों के परिवारों को कई कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए 'समर्थन बाई ओयो' नाम की एक पहल शुरू की है। ओयो ने एक बयान में कहा कि इस पहल के तहत भागीदारों के परिवारों की मदद के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें पांच साल के लिए दो बच्चों तक की शिक्षा का खर्च उठाना, और पतिध्पत्नी के लिए एवं एक बच्चे के लिए तीन साल तक पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा कवरेज शामिल है।

कंपनी टेकरेट का तीन महीने का कमीशन देने और रिकवरी शुल्क को माफ करने के अलावा, मृतक भागीदार के परिवार के योग्य सदस्यों को मेंटरशिप और इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगी। ओयो इंडिया और दक्षिणपूर्व एशिया के सीईओ रोहित कपूर ने कहा, 'हम ओयो के स्वतंत्र, छोटे होटल और घर के मालिकों के योगदान को मान्यता देते

हैं। ओयो के सैकड़ों भागीदार देश को क्वारंटीन, सेल्फआइसोलेशन और रहनसहन की जरूरतों से जुड़ी मदद देने के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आए। इनमें से कुछ होटल भागीदारों ने समाज और अपने ग्राहकों की सेवा करते हुए अपनी जान भी गंवा दी।' कपूर ने कहा कि यह ओयो की तरफ से उनके प्रयासों की सराहना करते हुए दिया जाने वाले छोटा सा योगदान है।

अपनी जिम्मेदारी और कमियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष डाल रही है दिल्ली सरकार: बिधूड़ी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेबवार्ता)। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ऑक्सीजन की कमी पर मौतों के मामले में आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी और कमियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष डाल रहे हैं। यहां 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कभी यह सूचना नहीं भेजी कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में भी यही कहा कि एक अस्पताल में हुई ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। इसके बाद अब दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है।

बिधूड़ी ने कहा कि स्वास्थ्य ट्रांसफर सब्जेक्ट है जिसमें सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी को जानबूझ कर तोड़मरोड़ कर पेश कर रही है। राज्यसभा में सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि कोरोना से हुई मौतों के बारे में राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश ही केंद्र सरकार को सूचनाएं मुहैया कराते हैं। इनमें से किसी भी सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को रिपोर्ट नहीं किया है। बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह कहीं नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई बल्कि यह कहा है कि राज्य सरकारों ने और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसकी सूचना केंद्र को नहीं दी। दिल्ली सरकार ने भी केंद्र को ऐसी किसी मौत की सूचना नहीं दी। बिधूड़ी ने कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार ने केंद्र को कोई सूचना नहीं दी और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की समिति ने भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से इनकार किया। जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई 21 मौतों के बारे में जब दिल्ली सरकार की कमेटी बनाने के लिए कहा गया तो दिल्ली सरकार ने ही इस कमेटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जिसमें साफसाफ कहा गया है कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में जो मौतें हुई, उनमें ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का कोई सबूत नहीं मिला। वे सारे मरीज दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे। अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपने पापों को दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर मृतक के परिजनों को पांचपांच लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया था।

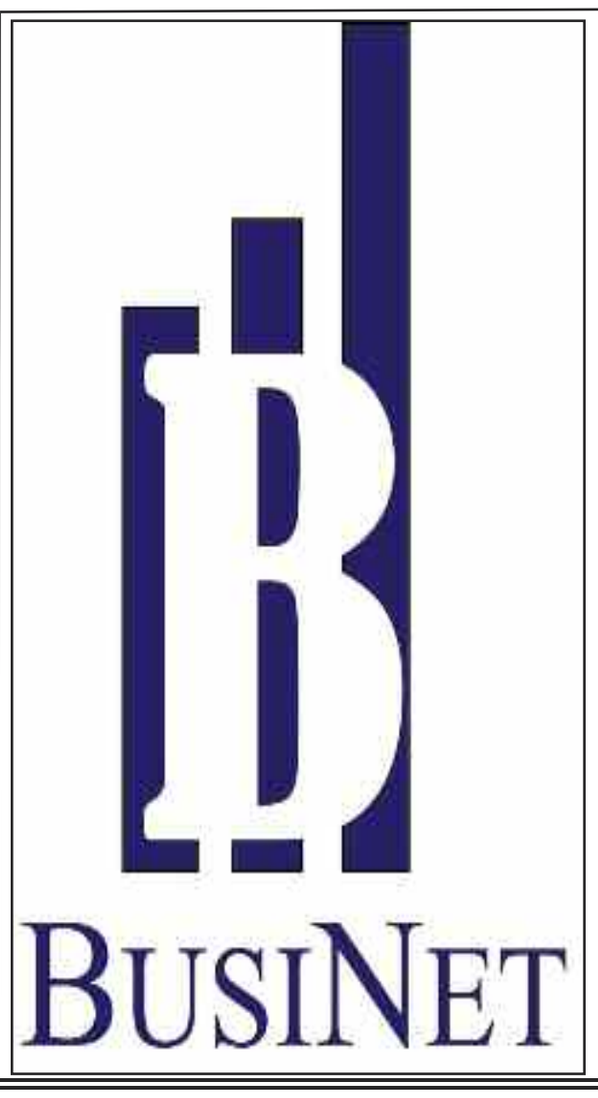

संपादकीय

स्वतंत्रता संग्राम में तिलक जी का योगदान

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आक्रोश का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष प्रकट करने के अनूठे तरीके निकाले थे। गणेश पूजा उनमें से एक थी। उस समय गणेशोत्सव धार्मिक कम और राष्ट्रीय पर्व ज्यादा था। बाल, लाल, पाल की त्रिमूर्ति की एक प्रमुख कड़ी थे लोकमान्य तिलक। तीनों, जिनमें पंजाब के लाला लाजपतराय, बंगाल के बिपिन चंद्रपाल और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, को 'बृहदत्रायी' भी कहा जाता था। तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को रत्नगिरि में हुआ था। तिलक के पिताजी का नाम गंगाधर शास्त्री और माता का नाम पार्वती बाई था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अपना करियर एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। कुछ समय बाद उनका स्थानांतरण पूना हो गया। 1871 में 15 वर्ष की आयु में तिलक का विवाह हो गया। तिलक की सारी पढ़ाईलिखाई पूना में हुई। तिलक ने प्रथम श्रेणी में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। अपनी कालेज की शिक्षा के दौरान वह प्रोफैसर बर्डस्वर्थ और प्रोफैसर शूट से काफी प्रभावित हुए। बर्डस्वर्थ ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया और शूट ने इतिहास तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इस दौरान जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वह उनके भावी जीवन में काम तो आया ही, उससे उन्हें अंग्रेजों के असली इरादों को समझने में भी सहायता मिली। तिलक राजनीति और मैटाफिजिक्स से संबंधित पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे। उन पर पश्चिमी विचारों का कितना प्रभाव था, यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। शिक्षा पूर्ण करने पर तिलक को अच्छीखासी सरकारी नौकरियों के ऑफर मिले थे, परंतु उन्हें ठुकराते हुए उन्होंने राष्ट्र एवं समाज में जागृति उत्पन्न करने के काम को ज्यादा महत्त्व दिया। तिलक की निश्चित धारणा थी कि आज की शिक्षा के आधुनिक सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा से ही आम जनता में चेतना आएगी और तभी ब्रिटिश साम्राज्य के असली इरादों को जनता समझ पाएगी।

अपने इस चिंतन के अनुकूल तिलक ने आगरकर, चिपलनकर और नामजोशी के सहयोग से एक इंगलिश स्कूल की स्थापना की और बाद में 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसायटी भी गठित की, परंतु कुछ मुद्दों पर गंभीर मतभेद होने के कारण उन्होंने इससे अपना संबंध तोड़ लिया। सच पूछा जाए तो इस सोसायटी से संबंध विच्छेद करने के बाद ही तिलक का असली सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। इस बीच तिलक ने 'केसरी' और 'मरहूटा' नामक दो अखबारों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। इनके माध्यम से तिलक के आकर्षक बहुरंगी व्यक्तित्व से आम लोगों का परिचय हुआ। तिलक ने 1904 में गायकवाड़ा नाम का भवन खरीदा। उसके एक हिस्से में वह स्वयं रहते थे और दूसरे हिस्से में उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित किया था। इसी छापेखाने में अखबार छाप कर ये देशवासियों में चेतना फैलाने का काम करते थे। अखबारों के प्रकाशन के साथसाथ वह सार्वजनिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। उनका काफी समय अध्ययन में ही जाता था। वह लगभग प्रति सप्ताह एक न एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते थे। तिलक का संपूर्ण जीवन 'कर्मयज्ञ' था। इस कर्मयज्ञ का मुख्य उद्देश्य उस राष्ट्र को जगाना था जो कुंभकर्णी निद्रा की स्थिति में था। अभूतपूर्व इच्छाशक्ति, परिश्रम और संगठन की असाधारण क्षमता का उपयोग कर उन्होंने राष्ट्र में एक नई चेतना का संचार करने का प्रयास किया। उनके इसी प्रयास के चलते उन्होंने यह अमर नारा दिया था कि 'स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा।' उनके इस नारे ने राष्ट्र के समक्ष एक मंजिल तय कर दी। तिलक ने बारबार घोषणा की थी कि उन्हें 'संपूर्ण स्वराज्य' चाहिए। उन्होंने अपनी इस अभूतपूर्व घोषणा को लंदन तक पहुंचाया। तिलक ने एक ऐसा काम किया जिसने उन्हें अमरत्व प्रदान किया है। वह काम है ।

हंगामे की भेंट चढ़ती देशवासियों की उम्मीदें

संसद के मानसून सत्र की शुरूआत हंगामे के साथ हुई है। विपक्ष संसद की कार्यवाही मे लगातार अवरोध पैदा कर रहा है। विपक्ष के चरित्र से इस बात की पूरी उम्मीद है कि आम जनमानस का कुछ भी भला इस सत्र में होने वाला नहीं है। जनता खाली हाथ थी और खाली हाथ ही रहेगी। हंगामा करके जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाली संसद में बड़ी निर्दयता और निर्लज्जता से देश का धन अपव्यय किया जा रहा है। संसद लोकतंत्र का वह मंदिर जिस की तरफ पूरे देश और देशवासियों को उम्मीदें, आशाएं और विश्वास होता है। पूरे देश की दृष्टि इस पर लगी रहती है। यही बैठकर हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे लिये कल्याणकारी नीतियां, कानून और भालाई के कार्य करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के समय मानसून सत्र में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो कोरोना महामारी के कहर के कारण निराश और टूट चुके समाज को एक और बड़ी निराशा की ओर धकेल रहा है। सरकार और विपक्ष में आरोपप्रत्यारोप की प्रथा कोई नयी नहीं है। इसमें दोनों को ही खूब आंनद भी आता है। लेकिन कोरोना महामारी का संकट सिर पर मंडरा रहा है। तीसरी लहर की आंशका जताई जा रही है। ऐसे में हंगामे और राजनीति के मध्य आम जनमानस की भलाई से जुड़े गंभीर और अति महत्व के विषयों की घोर अनदेखी हो रही है।

संसद का मानसून सत्र चल रहा है। संसद सत्र वह समय होता है जब देश भर के चुने हुए सांसद देश की राजधानी दिल्ली की ओर रुख करते हैं। रुख किया जाता है सत्र मे शामिल होने के लिए। रुख किया जाता है कि दिल्ली पहुंच कर अपने प्रदेश की जनता के लिए जितना हो सके किया जाए। यही कारण होता है वोट देकर सांसदों को संसद मे भेजने का भी। ताकि साल मे तीन बार जबजब संसद का सत्र शुरू हो तबतब आपके संसद जी वहां जाकर अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सांसद जी ऐसा क्यूं करेंगे ? क्योंकि वो ऐसा करने के लिए मोटा पैसा लेते हैं। लेकिन इतना पैसा लेने के बाद भी आजकल यह देखना आम हो गया है कि संसद फलाना समय के लिए स्थगित, तो ढिमकाना समय के लिए स्थगित। यहां से सांसद जी जाते हैं काम करने, वहां धरना, प्रदर्शन और

होहल्ले में मशगूल हो जाते हैं। अब वो पैसा जो उनके वहां जाने से खर्च हुआ वह किसका होता है? वह पैसा आपका और हमारा होता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 29 जनवरी से 9 फरवरी और 5 मार्च से 6 अप्रैल 2018 तक दो चरणों में चले बजट सत्र में 190 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए। यानी प्रति मिनट संसद की कार्यवाही पर तीन लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया। संसदीय आंकड़ों की बात करें तो 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे। इस दौरान 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिसमें 138 करोड़ संसद चलाने पर और 6 करोड़ सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास पर खर्च हुए। एक साल के दौरान संसद के तीन सत्र होते हैं। इसमें से भी अगर साप्ताहांत और अवकाश को निकाल दिया जाए तो यह समय लगभग तीन महीने का रह जाता है। यानी केवल 7080 दिन कामकाज होता है जिसमें भी संसद ठीक तरह से चल नहीं पाती है। इसे ऐसे समझिए कि संसद के एक घंटे की कार्यवाही पर 1.2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानि हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए। ये संसद मे होने वाले काम तीन सत्रों मे बटे होते हैं। एक सत्र 24 महीने का हो सकता है। लेकिन कुल महीनो मे से 57 महीने हीं काम के होते हैं। उनमे से कम से कम 2 महीने निकल जाते हैं सप्ताहांत अवकाशों मे। बाकी महीने सांसदों के हंगामे और बहिष्कार मे निकल जाते हैं। तो साल मे 60-70 दिन हीं वैसे बचते हैं जिनमे संसद काम कर पता हो।

यह पैसा कई चीजों पर खर्च होता है। जैसे सांसदों के वेतन पर, उनको मिलने वाले भत्तों पर, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्चों पर, उनके कर्मचारियों के वेतन के रूप मे, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं के ऊपर। पिछले कुछ आंकड़ों की तुलना करें तो आप यह देखेंगे कि बजट सत्र मे बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित घंटों के 20 फीसदी या 33 घंटे बहस होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस आंकड़े मे भारी गिरावट है। साल 2010 प्रोडक्टिविटी के नजरिए से सबसे खराब साल रहा। र्ष 2014 के बाद सबसे कम काम 2016 शीतकालीन सत्र में हुआ था।इस सत्र में सांसदों ने लगभग 92 घंटे के काम में व्यवधान डाला, जिसके कुल खर्च का अनुमान लगाया जाये, तो वो 144 करोड़ रुपयों का होगा। सबसे हैरानी की बात ये है कि पिछले कई सालों की तुलना में 2016 में संसद की कार्यवाही सबसे ज्यादा बार स्थगित हुई है। हर सत्र में लगभग 18 या 20 दिन संसद की कार्यवाही चलती है। राज्यसभा में हर दिन पांच घंटे का और लोकसभा में छह घंटे का काम होता है। वर्ष 2016 में पहले सत्र में हंगामे की वजह से 16 मिनट बर्बाद हुए, जिसकी वजह से 40 लाख का नुकसान हुआ, दूसरे सत्र में 13 घंटे 51 में 20 करोड़ 7 लाख का नुकसान, तीसरे सत्र में 3 घंटे, 28 मिनट कार्यवाही ठप्प में 5 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ। चैथे सत्र में 7 घंटे, 4 मिनट की बर्बादी में 10 करोड़ 60 लाख रुपये का नुकसान, पांचवें सत्र में 119 घंटे बर्बाद यानि 178 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ।

आशीष वशिष्ठ

www.womenexpress.in

मन की बात ने आकाशवाणी को दिया नया जीवनदान

23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना हुई थी। कालांतर में 1957 में यह आकाशवाणी के नाम से जानी गई। 94 साल के सफर में भारत की प्रसारण सेवा ने काफी उत्तार चढाव देखे है। आठवें दशक तक या यूँ कहे दूरदर्शन के आगमन तक आकाशवाणी ही शिक्षा, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र की सिरमौर थी।

उस दौरान घर घर में ही नहीं अपितु हर हाथ में रेडियो था और लोग इससे चिपके रहते थे। हर प्रकार की सूचना का संवाहक था रेडियो। 1980 के बाद संचार के आधुनिक साधनों के प्रादुर्भाव के साथ आकाशवाणी का प्रभाव घटता गया। लोगों ने रेडियो के स्थान पर टीवी को अपनाना शुरू कर दिया। इसी बीच 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात नामक एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। कोई माने या न माने मगर यह बिलकुल सच है की अपनी पहचान खोती आकाशवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम ने पुनर्जीवित कर नया जीवनदान दिया है। मोदी के लोकप्रिय शो 'मन की बात' ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ा दी है। एक वक्त था जब, यह आकाशवाणी है, ये शब्द सुनते ही बच्चे से बुजुर्ग तक रेडियो को घेर कर खड़े हो जाते थे। दूरदर्शन के प्रादुर्भाव से पूर्व यानि अस्सी के दशक तक रेडियो पर सुनाई देने वाली यह आवाज संचार के आधुनिक साधनों के बीच गायब सी हो गई थी। पहले भारतीय प्रसारण सेवा फिर आल इंडिया रेडियो और इसके बाद आकाशवाणी के रूप में रेडियो अस्तित्व में रहा। दूरदर्शन के बढ़ते प्रभाव ने इसकी उपयोगिता पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया, रही सही कसर निजी चैनलों और मोबाइल ने पूरी करदी। मगर हाल के वर्षों में जहां लोगों में रेडियो की चाह बढ़ी है, वहीं इसकी बिक्री भी तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ा दी है। कह सकते है इसे नया जीवन मिला है। यह सच है कि आकाशवाणी की साख कमजोर हुई है मगर आज भी यह अब भी देश में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच देश की 99.20 प्रतिशत आबादी तक है। देश के 92.6 प्रतिशत भूभाग को यह कवर करता है।

आकाशवाणी अथवा ऑल इंडिया रेडियो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से की गई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1957 में इसका नाम बदल कर आकाशवाणी रखा गया। सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के इरादे से 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया, जो देश की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी को शामिल किया गया है।

आकाशवाणी को हिंदी भाषा को जन जन तक पहुँचाने का श्रेय दिया जा सकता है। आजादी से पूर्व आकाशवाणी अनेकता में एकता का सशक्त माध्यम थी। एक दूसरे के पास इसी माध्यम से सारी जानकारी पहुँचती थी। आजादी के बाद प्रगति और विकास का एक मात्र सजीव माध्यम बना आकाशवाणी। बड़े बड़े नेता और महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी बात आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों के समक्ष रखते थे। प्रसारण का एक मात्र साधन होने से देश में इसकी महत्ता और स्वीकार्यता थी। मगर धीरे धीरे निजी क्षेत्र में प्रसारण माध्यम शुरू हुए। निजी चैनलों से चैबीसों घंटे समाचार और मनोरंजन की सामग्री प्रसारित होने लगी फलस्वरूप लोगों ने आकाशवाणी से मुंह मोड़ लिया। इससे आकाशवाणी बहुत थोड़े क्षेत्रों में सिमट कर रह गयी। मगर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसकी सुध बुध ली तब से इसका महत्त्व एक बार फिर बढ़ा। विशेषरूप से प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हुआ तब से एक बार फिर आकाशवाणी लोगों के सिर चढ़ गयी। हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी की 'मन की बात' हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं में प्रसारित होती है। मोदी अपने हर कार्यक्रम में राष्ट्रीय महत्त्व की बात उठाते है। इसके दो फायदे प्रत्यक्ष तौर पर हुए। एक तो मोदी अपनी बात शहरी और ग्रामीण जनता तक आसानी से पहुंचते है दूसरे आकाशवाणी के कार्यक्रम भी आम जनता में लोकप्रिय हुए है। गांवों में तो आज भी रेडियो सूचना और मनोरंजन का माध्यम है। अब रेडियो फिर से आमजन व घरों तक पहुंचने लगा है।

बाल मुकुन्द ओझा
मालवीय नगर, जयपुर ।
www.womenexpress.in

महिला हेल्पाइन

डीएमआरसी	155370
सीआईएसएफ	22185555
दिल्ली पुलिस	1091
दिल्ली सरकार	181
कहीं भी कभी भी	1090

हिंदी दैनिक वूमेन एक्सप्रेस

खबर एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें
चेम्बर नंबर-302, वधवा बिजनेस सेंटर, डी-288-89/10,
नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टैशन गेट नंबर -1,
विकास मार्ग, नई दिल्ली - 110092
मोबाइल : 07042999974/ 09013518518
प्रधान संपादक : खुशबू पाण्डेय
प्रबंध संपादक : विनोद मिश्रा
राजनीतिक संपादक : नीता बुधौलिया
विज्ञापन प्रबंधक : रिजवाना नसीम
कानूनी सलाहकार : लख़मी चन्द
www.womenexpress.in
Email : thewomenexpress@gmail.com

इंदौर कार्यालय

102 , राजानी भवन , हाई कोर्ट के सामने,एम् ,जी रोड , इंदौर (मध्यप्रदेश)
रजनी खेतान (ब्यूरो चीफ)
मोबाइल : 08770587699, 09826024018

प्रयागराज कार्यालय

17/33, महात्मा गांधी मार्ग
(माया बाजार) सिविल लाइन्स।
फोन : 05322560285
09415215390
प्रबंध संपादक : विनोद मिश्रा

हर मोबाइल धारक को आधुनिक तकनीकी के दुष्परिणामों से बचने सतर्कता जरूरी

भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की त्रासदी से धीरेधीरे निकलते और तीसरी लहर के भय के साए में भारत के करीब करीब सभी राज्य अनलॉक हुए तो कुछ राज्यों में बाढ़ और लैंडइसलाइन ने धावा बोला जो अभी त्रासदी में हैं।

इस बीच सोमवार दिनांक 19 जुलाई से शुक्रवार दिनांक 13 अगस्त 2021 तक चलने वाले मानसून सत्र जिनमें कुल 19 बैठकें होगी शुरू हुआ। जिसमें जनता को बहुत उम्मीद थी कि देशने कोरोना काल में विपत्तियों का सामना किया और पूरे विश्व ने मेडिकल संसाधनों की आपूर्ति कर भारत को सहयोग किया, अब के संसद सत्र में पक्षविपक्ष मिलकर अनेक विषयों पर रणनीतिक रोडमैप बनेंगे, संसद के समक्ष 38 बिलों पर चर्चा होगी और सकारात्मक पहल से कामकाज होगा। जिसमें आम जनता के हितमें काम होंगे...साथियों बात अगर हम संसद सत्र के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की 19 जुलाई 2021 की करें तो मैं और मेरा मानना है कि आम जनता भी बहुत हैरान, आश्चर्यचकित हुएकि एक पेगासस स्पाईवेयर रूपी तकनीकी जिन्न उदय हुआ और खूब हंगामा मचा। जिस तकनीकी सॉफ्टवेयर के बारे में अधिकतम जनता को जानकारी भी नहीं है और दोनों सदन स्थगित हो गए।फिर मंगलवार दिनांक 20 जुलाई 2021 को सदन की कार्यवाही पहले 12बजे तक फिर 2बजे तक स्थगित हुई और अंत में गुरुवार 22 जुलाई 2021 तक स्थगित कर दी गई...। साथियों मामला पेगासस स्पाईडर से 300 भारतीयों की जासूसी से जुड़ा था जिसमें पक्ष विपक्ष के अनेक तर्क थे कि,भारत को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश, संसद सत्र में पक्षविपक्ष मिलकर सरकार पर आरोपों की झड़ी, पेगासस स्पाइवेयर की करें तो यह एक मंगलवार 20 जुलाई 2021 को संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले, हाथों में तख्तियाँ और खिलौने वाले फ़ोन को कान पर लगाए, कुछ विपक्षी दल के सासंद, महात्मा गांधी

की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार का विरोध करते नज़र आए, जबकि राज्यसभा में कोरोना पर कुछ चर्चा हुई फिर वह भी हंगामेकी वजह से स्थगित हुई। हालांकि पीएम ने 20 जुलाई को ही शाम 6 बजे कोरोना पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और कुछ दलों को छोड़ बाकी शामिल हुए...। साथियों बात अगर हम इस पेगासस स्पाईवेयर की करें तो यह एक सॉफ्टवेयर है और पहली बार 2016 में सामने आया नाम, रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की बदौलत मिली। उन्हें कई एसएमएस प्राप्त हुए थे,जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका मानना था कि उनमें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे।

उन्होंने अपने फोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब के जानकारों को दिखाया, उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से मदद ली तो अंदेशा सही था। अगर एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज़ ने उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता, तो उनका आइफ़ोन मैलवेयर से संक्रमित हो जाता। इस मैलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया। लुकआउट के शोधकर्ताओं ने इसे किसी एंडपॉइंड पर किया गया सबसे जटिल हमला बताया। उसके बाद कोरोनाकाल में फिर सामने आया इसका नाम, पिछले साल कंपनी ने ऐसे सॉफ़्टवेयर के निर्माण का दावा किया था जो कोरोनावायरस के फैलने की निगरानी और इससे जुड़ी भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। इसके लिएमोबाइल फ़ोन डेटा का उपयोग करता है। एनएसओ के मुताबिक वो दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत कर रहा था और दावा किया था कि कुछ देश इसका परीक्षण भी कर रहे हैं...। साथियों बात अगर हम इस सॉफ्टवेयर की उत्पत्ति की करेंतो,पेगासस एक स्पाइवेयर है जिसे इसराइली साइबर सुरक्षा कंपनी बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफ़ोन, फ़ोन में डाल दिया जाए, तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफ़ोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्सट मेसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। पेगासस को किसी के भी फोन में बेहद गुप्त तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके

पेगासस स्पाईवेयर का बवाल

शिकार शख्स को भी इस बारे में कोई भनक नहीं लगती। पेगासस को फोन में इंस्टॉल करने का सबसे लोकप्रिय तरीका पिशिंग मैसेज भेजना है। पेगासस एक लिंक भेजता है और यदि उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है, तो उसके फोन पर मैलवेयर या निगरानी की अनुमति देने वाला कोड इंस्टॉल हो जाता है। वपेगासस को तब भी इंस्टॉल किया जा सकता है अगर शख्स के नंबर की जानकारी नहीं है।

एडवोकेट किशन
भावनानी गोंदिया, महाराष्ट्र ।
www.womenexpress.in

सुरेखा सीकरी: सख्त मिजाज दादी-सा असल जिंदगी में थी खुशमिजाज

लोकप्रिय टीवी शो 'बालिका वधू' सहित कई बड़े टीवी धारावाहिकों तथा बॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा रही जानीमानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट से 16 जुलाई को 75 साल की आयु में निधन हो गया।

वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2018 में उन्हें पैरालाइटिक स्ट्रोक आया था और 2020 में दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था, तभी से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। बॉलीवुड से लेकर छोटे परदे तक अपना सिक्का चलाने वाली यह दिग्गज अभिनेत्री अभिनय की दुनिया में 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक निरन्तर सक्रिय रही और दमदार अभिनय के लिए उन्हें अपने जीवनकाल में तीन बार 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

पहला राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 1988 में आई फिल्म 'तमस' के लिए, दूसरा 1995 में फिल्म 'मम्मो' के लिए और तीसरा 2018 में आई फिल्म 'बधाई हो' के लिए मिला था। इनके अलावा उन्हें एक फिल्मफेयर अवार्ड, एक स्क्रीन अवार्ड और छह इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुए। हिन्दी थिएटर में उल्लेखनीय योगदान के चलते उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया था।

आयुष्मान खुराना अभिनीत सुपरहिट फिल्म 'बधाई हो' में सुरेखा ने दुर्गा देवी कौशिक नामक दादी का यादगार किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और यह पुरस्कार लेने वह व्हील चेयर पर पहुंची थी। पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने कहा था कि इनाम मिलते हैं तो किसे खुशी नहीं होती लेकिन तब और ज्यादा खुशी होती, अगर मैं अपने पैरों पर खड़े होकर यह पुरस्कार ले पाती। फिल्म में गजराज राव और नीना गुप्ता ने उनके बेटे और बहू का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने जीतू (गजराज राव) की मां और नकुल (आयुष्मान खुराना) की दादी का ऐसा रोल निभाया था, जो सदैव अपनी बहू से मनमुटाव रखती थी लेकिन एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर वह उसी बहू के पक्ष में उठ खड़ी होती है, जब अधेड़ उम्र की उनकी बहू की नज़दीकी रिश्तेदार इस बात के लिए आलोचना कर रहे होते हैं कि वह इस ढ़लती उम्र में मां बनने जा रही है।

वैसे तो एक्टिंग की दुनिया की सबसे मंझी हुई खिलाड़ियों में शुमार सुरेखा ने अपने बहुत लंबे अभिनय कैरियर में थियेटर, फिल्मों तथा टीवी में एक से बढ़कर एक दमदार रोल किए और 1978 में इमरजेंसी पर बनी फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' से डेब्यू किया था लेकिन उन्हें घरघर में सबसे बड़ी पहचान दिलाई थी टीवी धारावाहिक 'बालिका वधू' ने, जिसमें उन्होंने सख्तमिजाज 'दादीसा' (कल्याणी देवी) का ऐसा किरदार निभाया था, जिसने उन्हें घरघर की दादीसा बना दिया था। यह सीरियल 'कलर्स' टीवी चैनल पर 2008 से 2016 तक ऑन एयर रहा। उनकी चर्चित फिल्मों में 'सरफरोश', 'नसीम', 'नजर', 'सरदारी बेगम', 'दिल्लगी', 'जुबैदा', 'रेनकोट', 'शीर कोरमा', 'घोस्ट स्टोरीज', 'देव डी', 'सलीम लंगड़े पे मत रो', 'तमस', 'मम्मो', 'हरीभरी', 'मिस्टर एंड मिसेज अय्यर', 'तुमसा नहीं देखा' प्रमुख थी जबकि लोकप्रिय सीरियल्स में 'परदेस में है मेरा दिल', 'महाकुंभ- एक रहस्य, एक कहानी', 'सात फेरे- सलोनी का सफर', 'केसर', 'बनेगी अपनी बात', 'एक था राजा एक थी रानी', 'कभी कभी', 'जस्ट मोहब्बत' इत्यादि शामिल हैं। 'मम्मो' में फय्याजी और 'सलीम लंगडे पे मत रो' में अमीना का उनका निभाया किरदार लोग कभी नहीं भूले। निर्देशक जॉन मैथ्यू मैथन उन्हें अपनी फिल्म 'सरफरोश' के जरिये व्यावसायिक सिनेमा में लेकर आए, जिसमें वह सुल्तान की मां बनी थी।

आखिरी बार उन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जोया अख्तर की फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' में देखा गया, जिसमें जाह्नवी कपूर ने मुख्य किरदार निभाया था। सुरेखा ने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कुछ मलयालम फिल्मों में भी काम किया।

वर्ष 1945 में उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा अल्मोड़ा और नैनीताल में पलीबढ़ी। उनके पिता एयरफोर्स में और माता शिक्षिका थी। लीक से हटकर काम करना पसंद करने वाली सुरेखा फिल्मों में आने से पहले लेखक और पत्रकार बनना चाहती थी लेकिन किस्मत को उनका अभिनेत्री बनना ही मंजूर था। उन्होंने 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से ग्रेजुएशन किया था।

योगेश कुमार गोयल
www.womenexpress.in

सोशल मीडिया बना सहारा

सोशल मीडिया एक बार फिर पल भर में एक छोटे से न्यूज़ को देश और दुनिया में प्रसारित करके किसीकी ज़िंदगी संवारने का सशक्त माध्यम बना है। कुछ दिन पहले जमशेदपुर की बच्ची तुलसी के वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद वैल्युएबल एडुटेंमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक अमेया हेटे, तुलसी की मदद को आगे आए। अगर हर होनहार बच्चे को कोई हाथ थामने वाला मिल जाए तो गरीब बच्चों की ज़िंदगी संवर सकती है।

कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़ साल से स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन क्लास के ज़रिए ही पढ़ाई का काम चल रहा है, ऐसे में कई गरीब बच्चे स्मार्ट फोन, लैपटॉप या टैब नहीं होने के कारण पढ़ाई से वंचित हैं। पर कहते है ना जहाँ चाह वहाँ राह मिल ही जाती है।

जमशेदपुर की 11वर्षीय तुलसी की पढ़ाई भी बंद हो गई, तो उसने फूटपाथ पर आम बेचकर स्मार्ट फोन खरीदने के लिए जरूरी रुपये का जुगाड़ करने का फैसला किया। सड़क किनारे आम बेचती तुलसी का किसीने विडियो बनाया और जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तो मुंबई के व्यापारी और वैल्यूएबल एडुटेनमेनर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमेया हेटे को उस बच्ची का पढ़ाई के प्रति लगाव पसंद आया। उन्होंने 12 आम एक लाख 20 हजार रुपये में खरीद लिए, यानी हर एक आम की कीमत

10 हजार रुपये तुलसी को दी गई।

अमेया हेटे ने बच्ची को न सिर्फ 13 हजार रुपये का मोबाइल दिलाया, बल्कि पूरे साल की पढ़ाई के लिए उसका इंटरनेट रिचार्ज भी करावा दिया। तुलसी अब मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेगी। तुलसी ने बताया कि स्कूल बंद होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गयी थी। जिससे उसे काफी खराब लग रहा था। इस कारण उसने आम बेचकर अपने लिए स्मार्ट फोन खरीदने का निश्चय किया।

बच्ची का नाम तुलसी है रविवार को झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी वह सड़क किनारे आम बेच रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया और पूछा कि वह आम क्यों बेच रही है, तो उसने सारी बात बतायी। इसके बाद मुंबई से किसीने उसे फोन कर पूछा कि क्या वह पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती थी, तो तुलसी ने पढ़ाई की इच्छा जतायी। जिसके बाद उनकी ओर से बड़ी सहायता दी गयी और एक आम की खरीद 10 हजार रुपये में करते हुए एक लाख 20 हजार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

तुलसी की मां पद्मिनी देवी ने बताया कि पैसे आने के बाद उन्होंने तुलसी के लिए ट्यूशन का भी इंतजाम कर दिया है। उन्होंने अमेया हेटे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब तुलसी को आम नहीं बेचने पड़ेंगे। वहीं तुलसी के पिता श्रीमल कुमार का कहना है कि इस बुरे समय में अमेया हेटे उनके लिए भगवान के रूप में आये और अब उनकी बेटी आगे की पढ़ाई कर सकेगी।

तुलसी ने पहले ही दिन ट्यूशन पढ़ने गयी शिक्षिका पर भी अच्छी छाप छोड़ी। शिक्षिका नेहा ने कहा कि तुलसी में पढ़ाई की ललक है और इसे सही मार्गदर्शन मिला, तो यह अपना और अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करेगी।

आज के दौर में कई बच्चों की पढ़ाई छूट गई है हर किसीकी मोबाइल, लेपटाप खरीदने की हैसियत नहीं होती, पर जिनके पास पैसे है वह लोग अगर इस तरह जरूरतमंदो की सहायता के लिए आगे आए तो देश का भविष्य सशक्त बन सकता है।

भावना ठाकर
भावु, बेंगुलूरु ।
www.womenexpress.in

ये दुनिया राम भरोसे

ये दुनिया राम भरोसे
कल क्या हो
किसको पता
कौन किसी को
कब तक रोके
ये दुनिया राम भरोसे

जीवन मरण
सब हाथ उसी के
कोई कैसे उसे टोके
समय की होनी
समय पर होए
कोई कैसे रोके
ये दुनिया राम भरोसे

पल भर में
मिल जाए माटी में क्यों
इतराएं हम मानव होके
ख़ाक से उठा कर
महल बिठा दे कभी
कभी कण भी ना होते
ये दुनिया राम भरोसे

भज ले मनवा
राम नाम को
जिव्हा को दे ना टोके
आज भजे तू
कल राम भजें तुझे
रहे ना खाली हाथ होके
ये दुनिया राम भरोसे

उषा सोलंकी
उज्जैन (मध्य प्रदेश)।
www.womenexpress.in

ये गिरी और कानन, ये झरनो से पुछो

ये गिरी और कानन, ये झरनो से पुछो
धरा पे क्या गुजरी, नभ से तो पुछो
ये कलरव सी करती, है सरिता का जल
ये साहिल पे बहते, शव से तो पुछो

ये काँले घने रूप, ये बादल से पुछो
निशाँ छा रहा क्यू, उजालो से पुछो
सुनहरी फसल पल में, झुलस क्यू गई
कृषक पे क्या गुजरी, उर वेदनाओं से पुछो

ये सागर की लहरो, ये नाँव से पुछो
ये उठते तूफानों की, गुंजन से पुछो
हवाओं का रूख, पल में बदल क्यू गया
ये कहर जिसपे ढाई, उस मानव से पुछो

ये उपवन के फूल, कलियों से पुछो
महकती फिज़ाओं के गुलशन से पुछो
ये भवरे पंखुड़ियो के, रस को चुराते
ये मीठी शहद को, मधुमक्खी से पुछो

प्रभात गौर
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)।
www.womenexpress.in

दुआओं का दरवाजा

बढ़े चलो, बढ़े चलो
अच्छे काम, तुम करते चलो
दीन दुखियों की, करो सहायता
बड़ो को तुम, सलाम करो

मिल जाए अगर, कोई भिखारी
पेट उसका भरते चलो
अगर हो किसी को, कोई बीमारी
दिला दवाई, आगे बढ़ो
बहन किसी की, बिप्ता में
मिल जाए, उसकी तुम
सहायता करो
अगर मिले, माँ बाप किसी का
उसको तुम, प्रणाम करो

इन सबके करने का तुमको
रत्ती भर फर्क, नहीं पड़ता
ये सब कुछ, जाकर तुम्हारे
कर्मों में, जमा हो जाता

जो तुम इस तरह, करोगे
तो तुम लाखों दुआएं पा लोगे
और अपने इस, छोटे से
जीवन में
द्वार, स्वर्ग का भी, खटका लोगे

करमजीत कौर
श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब ।
www.womenexpress.in

खुली किताब

हमारा राष्ट्रीय एक खुली किताब के जैसे हैं।
जिसमें हर धर्म को सम्मान से मनाया जाता है।
हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज सुहाने हैं।
राष्ट्र में खुशियों को मनाया जाता है।
पर दीन की जनता का दर्द भरा है।
गरीब के दिल को दिखाना।
सबसे बड़ा महापाप माना है।
चाहे कोई जाति धर्म क्यों ना हो।
यह खुली किताब सबकी है।
जिसमें ज्ञान सम्मान छुपा है।
कोई पढ़ कर देखिए जरा खुली किताब।
यह जिंदगी चार दिन की होती है।
सुकर्म करने को चार दिन बहुत होते हैं।
सभी धर्म ग्रंथों को मान्यता देना है।
सबको भाई भाई समझना है।
देशहित पर मर मिटने की।
सबको वसुदेव कुटुंबकम समझना है।
हमारा राष्ट्र में अनेकता में एकता है
यह एक प्यारी खुली किताब है
खुली किताब को पढ़ना, पढ़ाना है

संगीता चमोली
देहरादून, उत्तराखंड ।
www.womenexpress.in

शिव प्रेम हैं

शिव प्रेम हैं
शिव भक्ति हैं
शिव तांडव हैं
शिव शक्ति हैं।।
शिव सत्य हैं
शिव मंगल हैं
शिव शांति
शिव दंगल हैं।।
शिव ही गोचर
शिव अगोचर
शिव जग के कणकण में
और शिव ही कण के बाहर भीतर ।।
शिव ही अंबर
शिव हैं दिगंबर
शिव शुन्य हैं
शिव ही अभ्यंतर।।
शिव ही जीवन
शिव ही मृत्यु
शिव मोक्ष हैं
शिव ही मुक्ति ।।
शिव ब्रह्म हैं, शिव हैं बिहारी
शिव भोला हैं,शिव भंडारी
शिव ही हरते क्लेश हमारी
जयजय शंभू, जय नाथ तिहारी ।।

मुकेश सिंह
असम ।
www.womenexpress.in

लॉकडाउन में शादी का इफेक्ट

न बैंड बाजा, न डीजे
बस गिनेचुने थे बराती।
थम गई पैसों की बर्बादी,
बड़ी अनोखी हुई रें भाई !
लॉकडाउन की शादी।

आमत्रिंत हुए थे लोग कुछ कम
मुँह कोई फुलाए या पिचकाये
इसका किसी को न था टेंशन
सरकार के नियमों का हुआ था पालन
अपनी सुरक्षा पर आये,
आमंत्रण पर था मेंशन
कई दिनों के रस्मों को,
एकदो दिन में निपटा लिया
हाँ, झेली न प्रॉब्लम नयी जोड़ी ने
न झुकझुक कर प्रणाम किया।
रिश्तेदारों को गले न लगाया
दूल्हादूल्हन ने पश्चिमी सभ्यता अपनाया।

अब आप कुछ भी कह लो भाई
पर शादी न भाये बिन बारात
हाँलकि खर्च कम होता है
पर ऐसी शादी न रहती याद
वह महीनों की तैयारी
वह हफ़्ते भर की हँसीमजाक
वह हफ़्तों भर पहले रिश्तेदारों का आना
और परिवारों का प्यार
वह नटखट खेलते कूदते प्यारे बच्चे
इन सबका आनंद न पाया
रस्मे हुई सब सीधी साधी
अब आप कुछ भी कह लो भाई
बड़ी अनोखी हुई ये,
लॉकडाउन की शादी ।।

जय कुमार सिंह
दोयांगमुख, असम।
www.womenexpress.in

बेटियाँ ...

जाने कब बेटियाँ बड़ी हो जाती है,
अश्रुकूट सदा रही जो बनकर,
आँखों की नमी हो जाती है।
जीवन की रेखा का आरंभ वही है,
फिर क्यूँ बताई,पराई वह जाती हैं?
अभी अभी तो जैसे
वह जीवन में आई थी,
समेटे सारी खुशियाँ खुद में,
संग अपने वह लाई थी।
कैसे कह दूँ आज पराया
उसको मैं?
जीवन की मेरे वह संपूर्ण
कमाई थी।
तेरे सुंदर रुदन को जब,
पहली बार आभासा था।
यूँ लगता था जन्मोंजन्मों से,
मन मेरा यह प्यासा था।
चंचल नयन, तेजभान सी,
कोपल सम ये तेरी हथेली,
द्वारद्वार गुंजित हो उठते,
जब गूंजे तेरी अठखेली।
समझ न पाया गोद से कब,
कांधे तकआई मेरी लाडली।
तेरी सुंदर छवि को देख,
अक्सर उर उल्लास भरा।
पावस की बूंदो सी तुम हो,
मैं खेत हूँ हराभरा।
शब्दों में ना कर पाऊँगा,
परिभाषित मैं तुझे अनूपा।
जो रहा है तुझसे वंचित,
कहलाता वह भाग्य अछूता।
लताओं सम जब बढ़ने लगी,
व्याकुलता मुझमें थमने लगी।
समझ न पाया कारण यह मैं,
क्यूँ हद में वह रहने लगी।
कैसी रीति ये जगत में व्यापक,
तोड़ न पाए जिसे जनक तक।
कहते थे सिय प्राण हमारी,
कैसे सह गए वन गमन तक।
कभीकभी लगता है मुझको,
बोनसाई बना रहा हूँ।
बहुत वृहद स्वरूप है तेरा,
पर क्यूँ तेरे काट रहा हूँ।

शिल्पी सिंह बघेल
शहडोल, मध्यप्रदेश।
www.womenexpress.in

गुरु वंदना

गुरु चरणन में वंदन है
हमें अपना बना लेना
पकड़ के हाथ हे गुरुवर
हमें चलना सीखा देना
गुरु चरणन....

मिटा कर अज्ञानता मेरी
ज्ञान का दीप जला देना
देकर ज्ञान का हमें दान
हमें सद्ज्ञान करा देना
गुरु चरणन....

भूला कर दोष मेरे सारे
भव से पार करा देना
देकर ज्ञान का चक्षु
हमें आत्मज्ञान करा देना
गुरु चरणन....

कुमकुम कुमारी
योगनगरी मुंगेर, बिहार ।
www.womenexpress.in

लो शहर तुम्हारा छोड़ चले

आ ठहर गया उन राहों पर ,
जिन राहों की कोई मंजिल नहीं।
मिलती थी खुशियाँ मुश्किल से ,
आज जीवन में कोई साहिल नहीं।

फिरते थे अक्सर उन राहों पर ,
जिन राहों में थी प्रीत मिली ।
वो लौट गया उस जीवन में,
हमको तो बस रुसवाई मिले ।
चाहत की उन गलियों में ,
अब मारे मारे फिरते हैं ।
खो जाते हैं यादों में अक्सर ,
ठोकर खाकर गिरते हैं ।

क्या पाया चाहत करके हमनें,
आज खुद ही पर हंसते हैं ।
हो जाए कहीं ना कोई खता ,
इन बातों से हम डरते हैं ।

लो शहर तुम्हारा छोड़ चले ,
रहना यादों की गलियों में ।
आ ठहर गया उन राहों पर ,
जिन राहों की कोई मंजिल नहीं।।

पूनम शर्मा स्नेहिल
www.womenexpress.in

आस्था और विश्वास के नाम पर

सदियों से इंसान का शिकार
बनता रहा है जानवर,
जीभ का स्वाद व पेट की भूख
मूल में रही इन हत्याओं के पीछे
लेकिन जायज ठहराता रहा है इन्हें
इंसान अक्सर कभी किसी
परम्परा के नाम पर तो कभी
आस्थाविश्वास के नाम पर।

वैसे देखा जाए तो
बहुत सारे जीव हैं इस सृष्टि में
अपना पेट भरने के लिए
अपने से कमजोर जीवों पर निर्भर
लेकिन लेते नहीं हैं कभी वो
किसी जीव की जान
अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने
के नाम पर या फिर किसी
धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर।

सिर्फ इंसान में ही है यह प्रवृत्ति
कि वो अपने द्वारा की गई
हत्याओं को
लाजमी बताता है
कभी शौक पूरा करने के नाम पर
तो कभी अपने अस्तित्व को
बचाए रखने के नाम पर,
कभी अपनी जरूरतों के नाम पर
तो कभी अपने रीति रिवाजों को
बनाए रखने के नाम पर।

जितेन्द्र कबीर
चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।
www.womenexpress.in

देश पर मर मिटे, देश के जवान वीर

देश पर मर मिटे, देश के जवान वीर,
लहू था गरम और जोश की पहचान वीर,
भीड़ गये, लड़ गये, देश की शान वीर,
घरबार छोड़कर लुटा गये देशपर अरमान वीर !
आजादी के लिए कर्म था, वतन की आन के लिए जान देना धर्म था,
जोशओ खरोश था, लहू भी गर्म था,
दुश्मनों से लड़ने को लपलपाई शमशीर की चिंगारियां,
खुबहुई तैयारियां !
भेष बदलबदल कर दांत खट्टे कर दिये,
सिर काटकाट कर, धूलधूल कर दिये,
क्रांतिकारी बन गये, तब मिली आजादी थी,
सभी का जोश था, सम्मिलित योगदान था,
सबको याद आ रहा,
क्रांतिवीरों का बलिदान था !
आज की पीढ़ी को उन्हें समझना आसान नहीं,
मादरेवतन की शान में कटना आसान नहीं,
फिर भी जोश, जोश है, धधक रही ज्वाला वहीं,
ये खून भी इसी देश का क्रांतिवीरों वाला सही !

मदन वर्मा
इंदौर, मध्यप्रदेश ।
www.womenexpress.in

तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ

है अजब कहानी जीवन पथ की,
तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ
ठहरो न तुम इक भी पल यूँ,
राह पकड़ बस चलते जाओ।।

शूल मिलें तो फूल समझना,
न बाधाओं से है घबराओ।
दृढ़ निश्चय को मंत्र बनाकर,
है फूलों से तुम राह सजाओ।।
हो लगनशील, मेहनत तुम करना,
कठिन परिश्रम को और बढ़ाओ।
लक्ष्य भेदकर ही दम लेना,
है विजय पताका तुम लहराओ।।

है लक्ष्य सदा सर्वोपरि रखना,
न चिंताओं को और बड़ाओ।
समय से सीख है सदा सीखना,
बस राह पकड़ तुम बढ़ते जाओ।।

अरमानों को है ऊँचा रखकर,
है नभ से भी ऊँचे बढ़ते जाओ।
मान बढ़ाना अपनों का तुम,
है जगत मैं इतना नाम कमाओ।।

अवधेश कुमार मौर्य
पोरसा, मुरैना (मध्यप्रदेश)।
www.womenexpress.in

सफर में धूप तो बहुत होगी

सफर में धूप तो बहुत होगी तप सको तो चलो,
भीड़ तो बहुत होगी नई राह बना सको तो चलो।
माना कि मंजिल दूर है एक कदम बढ़ा सको तो चलो,
मुश्किल होगा सफर, भरोसा है खुद पर तो चलो।

हर पल हर दिन रंग बदल रही जिंदगी,
तुम अपना कोई नया रंग बना सको तो चलो।
राह में साथ नहीं मिलेगा अकेले चल सको तो चलो,
जिंदगी के कुछ मीठे लम्हे बुन सको तो चलो।
महफूज रास्तों की तलाश छोड़ दो धूप में तप सको तो चलो,
छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढ सको तो चलो।
यही है ज़िन्दगी कुछ ख़्वाब चन्द उम्मीदें,
इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो।
तुम ढूंढ रहे हो अंधेरो में रोशनी,
खुद रोशन कर सको तो चलो,
कहा रोक पायेगा रास्ता कोई
जुनून बचा है तो चलो।

जलाकर खुद को रोशनी फैला सको तो चलो,
गम सह कर खुशियां बांट सको तो चलो।
खुद पर हंसकर दूसरों को हंसा सको तो चलो,
दूसरों को बदलने की चाह छोड़ कर, खुद बदल सको तो चलो।

अदित्य मिश्रा
दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली ।
www.womenexpress.in

आया चौमासा

गीत गा रहा चौमासा
अब,आसमान शोभित है।
बहुत दिनों के बाद धरा
खुश,तबियत आनंदित है।।

गर्मी बीती आई वर्षा,
चार माह चौमासा।
कभी धूप,तो कभी नीर है,
आशा और निराशा।।

वरुणदेव की दया हो गई, हर
प्राणी पुलकित है।
बहुत दिनों के बाद धरा खुश,
तबियत आनंदित है।।
स्रोत नीर के सूख गए थे,
रुकने को साँसें थीं।

नित्य उदासी में मन रहता,
गढ़ती नित फाँसें थीं।।

बारिश की बूँदों से पर
अब,मिला खुशी का ख़त है।
बहुत दिनों के बाद धरा
खुश,तबियत आनंदित है।।

बेचैनी में मन खोया था,
देह हुई थी बेदम।
पीर,वेदना बहुत बढ़ी थी,
सता रहा था नित ग़म।।

इन मेघों का अभिनंदन
है,लगता सुखद सतत् है।
बहुत दिनों के बाद धरा
खुश,तबियत आनंदित है।।
बहा पसीना रोज़ अनवर,
अब पावस का गायन।
जल की बूँदें करतीं देखो,
मौसम का अभिनंदन।।

सकल उदासी विदा हो गई, हर
पल उल्लासित है।
बहुत दिनों के बाद धरा
खुश,तबियत आनंदित है।।

सूखा है तो,बाढ़ कहीं है,
सड़कों पर है पानी।
चौमासे की भैया देखो,
बिलकुल अलग कहानी।।

तीज और त्यौहार महकते,पावन
शय हर्षित है।
बहुत दिनों के बाद धरा
खुश,तबियत आनंदित है।।

प्रो शरद नारायण खरे
मंडला (मध्यप्रदेश)।
www.womenexpress.in

रोज मनाता जश्न

शेर ने किया सोच कर ,
मंत्री पद विस्तार,
हरदिन हो बकरी नई ,
मंत्री पद पे यार ,
मंत्री पद पे यार ,
रोज नव बकरी आती .
और पुरानी यार ,
शेर की क्षुधा मिटाती ,
जंगल का कानून
लगाता न्याय में देर
रोज मनाता जश्न,
राज्य में हर दिन शेर।

महेंद्र कुमार वर्मा
भोपाल, मध्यप्रदेश ।

लगाए दिल को किसी के लगाव में रखना

लगाए दिल को किसी के
लगाव में रखना
फ़क़त है ख़ुद को हमेशा तनाव
में रखना

बड़ा अजब है ज़माना है कहता
इश्क़ इसे
किसी के दिल से दिल अपना
मिलाव में रखना

जो सब को खींच ले दीवाना
कर के अपनी तरफ़
वो हुस्न अपनी ग़ज़ल के रचाव
में रखना
है मेरा मश्विरा थोड़ी सी नर्मी
ऐ हमदम
तुम अपनी जिन्सेमोहब्बत के
भाव में रखना
पता है जिस में है अख़लाक़
क़ीमती है बहुत
मगर ये पलड़ा हमेशा झुकाव
में रखना

न झूमर और न गुलदान की
ज़रूरत है
मुझे तो उस को है घर के
सजाव में रखना
इस अपने हुस्न के जाहोजलाल
के दम पर
तुम्हें तो सिर्फ़ है आता दबाव
में रखना

तू जिस को फ़ैसलएतकेंकुर्ब
कहता है
ये तो है सैलेलहू को जमाव
में रखना

जकी तारिक बाराबंकवी
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
www.womenexpress.in

कोविड के भय से भारत के 20 खिलाड़ी और छह अधिकारी ही भाग लेंगे उद्घाटन समारोह में

(विशेष संवाददाता)

तोक्यो, 22 जुलाई । कोविड19 जुड़ी चिंताओं और अगले दिन कुछ प्रतियोगिताओं के आयोजन के कारण भारत के सात खेलों के 20 खिलाड़ी और छह अधिकारी ही शुक्रवार को यहां ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। भारत के अधिकतर खिलाडियों ने इस समारोह से दूर रहने का फैसला किया है। निशानेबाजी, बैडमिटन, तीरंदाजी और हॉकी जैसे खेलों के खिलाड़ी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि भारतीय दल अपने खिलाडियों को वायरस के जोखिम से बचाना चाहता है।

वैसे भी अधिकतर खिलाडियों को शनिवार से अपनी स्पर्धाओं में भाग लेना है। हॉकी से केवल ध्वजवाहक और पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिह समारोह में भाग लेंगे। जो 20 खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे उनमें मनिका बत्रा और अचंता शरत कमल सहित टेबल टेनिस के

चार खिलाड़ी तथा नौकायन टीम के भी इतने ही खिलाड़ी शामिल हैं। तलवारबाज सी ए भवानी देवी, जिम्नास्ट प्रणति नायक और तैराक साजन प्रकाश के अलावा आठ मुक्केबाज भी उदघाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम ध्वजवाहक हैं। उनके अलावा सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, आशीष कुमार और सतीश कुमार समारोह का हिस्सा होंगे भारत के 125 से अधिक खिलाड़ी तोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और भारतीय दल में 228 सदस्य हैं जिनमें अधिकारी, कोच, सहयोगी स्टाफ और वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिदर बत्रा ने कहा, ''तीरंदाजी, जूडो, बैडमिटन, भारोत्तोलन, टेनिस, हॉकी निशानेबाजी के खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें 24 जुलाई को प्रतियोगिताओं और अभ्यास सत्र में भाग लेना है। उन्होंने कहा, ''मार्च पास्ट जापानी वर्णमाला के अनुसार होगा और भारत का नंबर 21वां है। दोनों ध्वजवाहक एम सी मैरीकॉम और मनप्रीत सिह उदघाटन समारोह में भाग लेंगे। जो अधिकारी समारोह में हिस्सा लेंगे उनमें भारत के दल नेता बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, उप दल नेता प्रेम वर्मा, टीम चिकित्सक डा. अरुण बासिल मैथ्यू, टेबल टेनिस टीम के मैनेजर एमपी ड्क्षसह, मुक्केबाजी कोच मोहम्मद अली कमर और जिम्नास्टिक कोच लाखन शर्मा शामिल हैं।

टीम इंडिया के चीयरलीडर बने अक्षय कुमार

(विशेष संवाददाता)

मुंबई, 22 जुलाई । जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए इंडिया की टीम टोक्यो पहुंच चुकी है। इसी बीच बॉलिवुड ऐक्टर अक्षय कुमार ने टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह चीयर करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में ओलंपिक खेलों में टीम इंडिया को चीयर करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अनुराग ठाकुर ने अक्षय कुमार को नॉमिनेट किया था। अब अक्षय ने अनुराग ठाकुर को रिप्लाई करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह इंडियन टीम की हौसला अफजाई

करते नजर रहे हैं। वीडियो में अक्षय कह रहे हैं,'टोक्यो ओलंपिक में हमे अपने जाबांज खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रोत्साहन और दुआ से हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी टीम है आप सब अक्षियन। अक्षियन आप भी अपना वीडियो बनाइए और अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो में टैग करिए और हैशटैग चीयर फॉर इंडियन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अक्षय वीडियो में आगे कहते हैं,'भारत की जीत भारत के हाथों में है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय की अगली फिल्म 'सूर्यवंशी' है। जिसमें अक्षय के साथ कटरीना कैफ नजर आएंगी। इसके अलावा अक्षय 'बेल बॉटम', 'अतरंगी रे', 'पृथ्वीराज', 'बच्चन पांडे', 'राम सेतु' और 'रक्षा बंधन' में भी दिखाई देंगे।

कोरोना महामारी से उपजी आर्थिक संकटों का सामना कर रहे कलाकारों की सहायता के लिए अभिनेता अक्षय आगे आकर 50 लाख रुपये का सहयोग करते हुए कला जगत की अन्य तमाम हस्तियों से इसके लिए आगे आने की अपील की है। अक्षय ने कलाकारों की सहायता के लिए संस्कार भारती द्वारा चलाए जा रहे पीर पराई जाणे रे अभियान को समर्थन करते हुए एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि कलाकारों के सामने आर्थिक समस्या पैदा कर दी है।

तोक्यो के स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपये देगा आईओए

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह तोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देगा और इसके अलावा प्रत्येक भागीदार राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) को बोनस के तौर पर 25 लाख रुपये देगा। आईओए की सलाहकार समिति ने रजत पदक विजेताओं को 40 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है। आईओए ने बयान में कहा, ''इसमें तोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को एक लाख रुपये देने की भी सिफारिश की गयी है। आईओए ने इसके साथ ही प्रत्येक भागीदार

एनएसएफ को 25 लाख रुपये और पदक विजेता एनएसएफ को 30 लाख रुपये का अतिरिक्त सहयोग देने के समिति के निर्णय को स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों में से प्रत्येक को 15 लाख रुपये का सहयोग मिलेगा। आईओए महासचिव राजीव मेहता ने कहा, ''पहली बार आईओए पदक विजेताओं और उनके एनएसएफ को पुरस्कृत करने जा रहा है।' सलाहकार समिति ने भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य के लिये तोक्यो प्रवास के दौरान प्रतिदिन 50 डॉलर का भत्ता देने की भी सिफारिश की है। आईओए ने इसके साथ ही कहा कि सदस्य राज्य ओलंपिक संघों में से प्रत्येक को राज्य में बुनियादी खेल ढांचे को विकसित करने और अधिक खिलाडियों को खेलों से जोडने के लिये 15 लाख रुपये दिये जाएंगे।

कोरोना संक्रमण से उबरे पंत टीम के साथ बायो बबल में जुड़े

डरहम, 22 जुलाई । भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना संक्रमण से उबरकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से पहले टीम के बायो बबल में शामिल हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाये गए पंत ने दस दिन का पृथकवास पूरा कर लिया है। उनकी दो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। बीसीसीआई ने पंत की तस्वीर के साथ गुरूवार को ट्वीट किया, ''हैलो ऋषभ पंत। आपको वापिस लेकर अच्छा लगा।'' पंत अपने एक परिचित के घर पर रह रहे थे जब वह पॉजिटिव पाये गए। सूत्रों के अनुसार वह दांत के डॉक्टर को दिखाने के बाद डेल्टा 3 वैरिएंट से संक्रमति हुए थे। पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि स्टेडियम में यूरो फुटबॉल चैम्पियनशिप मैच देखने के बाद उन्हें संक्रमण हुआ था। भारतीय टीम को पत्र लिखकर विम्बलडन और यूरो मैचों में भीड़भाड़ से बचने का अनुरोध किया था।

नेहा ने कहा गायिका बनने के लिए कभी भी बुरा समय नहीं होता

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेबवार्ता)। नेहा कक्कड़ तेजी से वन वुमन इंडस्ट्री के रूप में उभर रही हैं, जो लगातार हिट गाने दे रही हैं और वर्तमान में शीर्ष पर चल रही हैं।

उनका कहना है कि इंडस्ट्री में सिंगर बनने के लिए कभी भी बुरा समय नहीं होता है। पिछले वर्षो में, उन्होंने बैकटूबैक हिट गाने दिए हैं जिसमें गर्मी, दिलबर और ओ साकी साकी जैसे फिल्मी गाने शामिल हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह इंडस्ट्री में एक गायिका बनने का अच्छा समय है, नेहा ने आईएएनएस को बताया, इंडस्ट्री में गायक होने का कभी भी बुरा समय नहीं होता है। यह मायने रखता है कि आप कितने यूनिक हैं, लेकिन सबसे बढ़कर, यह महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छे इंसान भी हों। संगीत उद्योग में हमारे सभी दोस्त वास्तव में अच्छे हैं और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। नेहा बहुत ही कम समय में रीमिक्स की निर्विवाद रानी बन गई हैं। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने से पहले, नेहा और उनके भाईबहन टोनी और सोनू कक्कड़ जागराता में गाया करते थे। नेहा ने कहा कि यह कड़ी मेहनत और ईमानदार का नतीजा है। यात्रा विनम्र रही है और यह मेरे लिए बहुत मूल्यवान है कि हम कैसे बढ़े हैं। मेरे प्रशंसक मेरी यात्रा को इसके लायक बनाते हैं। सफलता के साथ आलोचना आती है।

भोजपुरी लघु फिल्म लूट मार 4 ने मचाया धमाल

नई दिल्ली। आज जहाँ सिनेमा जगत में क्षेत्रिए भाषाओं की लघु फिल्मों में बाढ़ आई है, वहीं भोजपुरी फिल्म निर्माता भी किसी से पीछे नही हैं। अभी हाल में भोजपुरी लघु फिल्म लूट मार 4 के रिलीज होने से भोजपुरी फिल्म प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में गांव के एक दबंग की भूमिका में वासुदेव पासवान तथा उनके पुत्र की भूमिका में पवन परदेसी हैं। इस फिल्म में दर्शाया गया है कि किस प्रकार दबंगई दिखाकर लोगों से हफ्ता वसूली की जाती हैं तथा उनके गुंडे वहां की लड़कियों पर किस प्रकार बुरी नजर डालते हैं। अजय माइकल के बैनर तले बनी भोजपुरी लघु फिल्म लूट मार 4 में अजय माइकल, प्रिया यादव, राजन खत्री, आकांक्षा उपाध्याय, अमन पंडित, पवन परदेशी, वासुदेव पासवान मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अन्य कलाकार भी लघु फ़िल्म में बढ़िया अभिनय करते दिखेंगे। इस फिल्म को संगीत बद्ध किया है आतिशी तिवारी, अंतरा सिंह एवं प्रियंका, इस फिल्म के लेखक हैं पंडित प्रेमी तथा कैमरा मैन सलमान नाईस हैं।

कौन है अपना

कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास
जब रक्षक भक्षक बन जाये
कैसे चले देश की राज
कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास
गद्दारों की फौज खड़ी हो
कौन बचाये राष्ट्र

कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास
अलगाववाद अट्टाहस करता
राष्ट्र किससे करे फरियाद
कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास

हर जन को खुश रखना चाहूँ
पर हो जाता है नाराज

कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास
जब कातिब का चेहरा घिनौना
कौन लिखे इतिहास
कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास
जिसपर हमने भरोसा जताया
खंजर चुभोया है आज
कौन है अपना कौन पराया
किस पर करूँ विश्वास
धरती के दानव ने मिलकर
रच डाला है जग का विनाश

कौन है अपना कौन पराया
किसपर करूँ विश्वास
जिनको हमने सगा समझा था
उसने ही लुटा हमे आज

उदय किशोर साह
बाँका, बिहार ।
www.womenexpress.in

मेघा आए

काले काले घुँघराले मेघा आए,
संग में बरखा रानी को लाए ,
मेघों का आगमन होते ही

गाँवो में चारों ओर बहार आयी,
मेघों के स्वागत में ...।

मंद मंद पवन चलने लगी,
कोकिला कुहू कुहू करने लगी ,
मोर पंख फैला नाचने लगे,
दादुर टर्र टर्र करने लगे ,

सभी नाचने गाने लगे,
इठलाती बलखाती ...।

बरखा रानी भी नाचने लगी ,
रिमझिम रिमझिम फुहारें आयी,
झमाझम बारिश होने लगी ,
किसानों के चेहरे खिल उठे,

किसानों ने हल उठा लिए ,
खेतों की और चल पड़े,
नदियों तालाबों ने भी घूँघट निकाला,
पेड़ पौधे ने भी हरियाली ओढ़ ली,

चारों ओर जग में बहार आयी
मेघ राज आए संग बरखा
रानी लाए ।

मंजुलता
जोधपुर (राजस्थान)।
www.womenexpress.in

वृक्षारोपण

वृक्षारोपण पर ध्यान दें यह
जीवन की आवश्यकता है,
आधुनिकता के जीवन में
वन उपवन का नाश किया,

लोभी मानव ने पर्यावरण
को बलि चढ़ाया, अपने स्वार्थ
के लिए,
प्रकृति का दुश्मन मानव हो गया
अपनी सुविधाआराम में खो गया,
मानव के लालच में मानव,
खुद दुविधा में हो गया !

नेहा ठाकुर,
इंदौर, मध्यप्रदेश ।
www.womenexpress.in

भाग्य विधाता

तू जब चले उस राह पर
जहां न हो कोई संगी साथी
न घबरान भयभीत हो
अगर होगी लग्न सच्ची
कारवां चलेगा साथ तुम्हारे
सफलता की परवाह न कर

सफलता तेरी राहवर होगी।
आए कोई बाधा राह में
हौसला न हार कभी
नाकामी न रोक सके राह तेरी
न डिगे विश्वास तेरा
अपने हौसले से
दूर कर ले हर विघ्नबाधा
क्या हुआ जो साथ न दे कोई
तेरा हिम्मत और साहस है संग तेरे
इसके सहारे पार कर ले
मुश्किलों के पर्वत
और बन जा अपना भाग्य विधाता!!

विभा कुमारी
www.womenexpress.in

शिकायत

क्या बादल
इंसानों से बात नही करते
बेचैन निगाहे
ताकती बादलों को।
मन ही मन दुआएं
माँगती ऊपर वाले से
बादलों से कहे की बरस जा
काले घन को देख
मयूर नाचता
पीहू पीहू बोल मनाता।
बादलअपना अभिमान
दुनिया को दिखाता, गर्जन कर
बिजलियां चमकाता।
ये देख रहवासी
बरसने की अर्जियां
वृक्षों हवाओं से
मौसम की कोर्ट में लगाने लगे।
वृक्षो ने खिंचे
बादलों को अपनी ओर
हवाएं टकराने लगी
बादलों को आपस में।
वृक्ष ,हवाओं ने

छेड़ दिया युध्द बादलों से
अभिमान हुआ खत्म
झुकना ही पड़ा
आखिर बादलो को।
खेतों की फसलों का
गुस्सा हुआ थम।
सब ने मिलकर की
बादलों पर कार्यवाही
जब भी घुमडो
हमारे सर पर बरसना जरूर।
अबकी बार
ऐसा नही करोगे तो
घन श्याम से करेंगे
तुम्हारी शिकायत ।

संजय वर्मा
मनावर (धार) मध्यप्रदेश ।

पवित्र बन्धन

इबादत करूं मैं अल्लाह की
रात की चान्दनी देखूं तबसे
मुकम्मल दास्तां की धरोहर में
ख्वाबों के सपनों मैं, सजाऊं कैसे ?

प्रेम भाव के आलिङ्गन में समाऊं
तन मन ह्रदय में छा जाऊं सन्सार
हजरत मोहम्मद के पैग़ामों से
जनजन भाईचारा का सन्देश जगाऊं

विजय सन्देश पवित्र बन्धन है
ईदों के त्यौहारों का तोहफा विस्मित
क़यामत दलहीज खुदा कुर्बान मैं
दस्तूर है मुबारकबाद का अपना

कणकण से होता जगजीवन निर्माण
खुदा है जो करता विश्वकल्याण
मानवीयता बना जन्नत दरवाजा
महफूज़ रहूं सदा भवजाल से

शशि शहञ्शाह फरिश्ता अपना
मोहब्बत सरताज सरफरोशी सरसी
हो जाऊं प्रभा तम तिमिर में
घनघन घनश्याम बून्दबून्द बने हम

वरुण सिंह गौतम
रतनपुर बेगूसराय, बिहार ।
www.womenexpress.in

नारी इंसाफ मांगती है

मैं नारी हूं,
सदियों से अपने अस्तित्व के लिए,
लड़ती आई हूं,
पुरुषत्व के दंभ को सदा हीं,
अपने सर ओढती आई हूं,
मुझे मिल ना सका आज भी इंसाफ,
समाज के हुक्मरानों से,
जन्म से पहले हीं मां के गर्भ में,

मौत की सजा पाई हूं,
हां, मैं नारी हूं।
इस धरती पर जिसे हमने,
दर्द सह कर भी है जन्म दिया,
उसी ने हमारी अस्मिता को,
पल भर में हैं तारतार किया,
समानता का ढोंग रचा कर,
करते हैं वो हम पर वार,
देकर दुहाई प्रेम का,
हर बार हीं हमसे छल किया,
अब नहीं सहूंगी कोई भी दर्द,
कि तेरे हर रंग को पहचान
गई हूं,
इंसाफ हमें देना हीं होगा,
कि हर जंजीर को तोड़ आई हूं,
हां, मैं नारी हूं।

रंजना लता (ए.एन.एम)
समस्तीपुर, बिहार ।
www.womenexpress.in

जिंदगी हम आएंगे जरूर

अगर समंदर है तो
सुनामी बन कर आएंगे
अगर दरिया है तो
मीठा पानी बनकर आएंगे
रास्ते तो टकराते रहेंगे
जिंदगी के हर मोड़ पर
उम्र के बढ़ते कारवां में
फिर से जवानी बनकर आएंगे
जिंदगी डूबेगी
उदासियों के गर्त में
खुशियां छुपी छुपी होंगी
जाने कितने पर्त मे

सारी हरारतो को सोख
नई उमंग उम्मीदों की
रवानी बन कर आएंगे
जब भी उलझेगी जिंदगी
संसार के धूप छांव में
थकाएगी जिंदगी
जब भी मन के गांव में
सारी तकलीफों को
समेट करके
आंखों में रंग भरने खातिर
खुशियों की दुआ
आसमानी बनकर आएंगे
जब कहने को कुछ भी
लफ्ज नहीं होंगे पास
जब खो चुके होगे
जिंदगी के एहसास
लगाकर गले से
रो लेना हमको जी भर
तसल्ली से भरी हुई
आंखों का खारा पानी बनकर आएंगे

रेखा शाह आरबी
बलिया, उत्तर प्रदेश ।
www.womenexpress.in

जनसंख्या नियंत्रण

बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या भारतीय समाज हीं नही वरन संपूर्ण विश्व के लिए अभिशाप बनता जा रहा । जहाँ सीमित संसाधन की उपलब्धता और बेतहाशा बढ़ती आबादी एक दोनो को विपरीत दिशा में खिंचते जा रही है।

वहीं ईस राशाकशी मानव की आनेवाली भविष्य को अंधकार की और लगातार धकेलते जा रही है।

एक तरफ जहाँ बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है और सुविधाओं का लगातार ह्रास हो रहा है ऐसे में लोगो मे जागरूकता नितांत ही जरूरी है। हममें और जानवरों में कम से कम बुनियादी अंतर जरूर होना चाहिए कि अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें और आने वाले भविष्य को सुरक्षा और उचित संसाधन मुहैया कराए। यह मेरा या आपका नैतिक कर्त्तव्य है अपने संतानों को बुनियादी सुविधा अवश्य दिलाएं नही तो पशु और मानव में ज्यादा फर्क नही रह जाएगा।

पिछले कई दसक से प्रशासन के लगातार आवाह्न पर भी अगर हम नही जग पाए तो ये जरूरी की कोई ठोस कानून बने और उसका पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

इसके दायरे में समाज के सभी वर्ग, समुदाय ,जाती और धर्म को लाकर बिना किसी भेदभाव के समान कानून लागू कर पालन के लिए बाध्य करने की जरूरत।

समझने या समझाने की जरूरत, वर्तमान से भविष्य का गहरा रिश्ता है अगर आज सुरक्षित तो कल का उज्जवल भविष्य ,और अगर आज हीं सुरक्षित नही तो कल चमकदार भविष्य कैसे हो सकता है?

अंत मे
मैं जागूँ आप जागें और जागे समाज
मानव वाला धर्म दिखा कर
गढ़ लें एक नवीन इतिहास
नारा एक बुलंद कर
सुरक्षित करें समाज।।

कमलेश झा
नगर पारा भागलपुर ।
www.womenexpress.in

राज कुंद्रा एक धंधेबाज

वैसे यह खबर हमारे और आपके लिए एक सनसनी खबर हो सकती है पर उनके लिए ऐसी खबर रोजमर्रा में शामिल है जो नाक तक नर्क में डूबे हुए हैं। मेरा मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्यों?

हां, तो राज कुंद्रा जी यानि कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा जी के पतिदेव ।यार, हमने तो तुमको बिजनेसमैन समझा था पर तुम तो नंबरी धंधेबाज निकले ।जब तक तुम बिजनेसमैन थे तब तक सुलझे हुए इंसान लग रहे थे पर जबसे तुम्हारी धंधेबाजी सामने आई है तबसे तुम काफी उलझे हुए लग रहे हो। राज कुंद्रा तुम अचानक से उसी तरह सुर्खियों में आ गए जैसे कोरोना महामारी सुर्खियों में आई थी।

तुम्हारी पत्नी कह रही थी करो
कपाल भाती
और तुम बना रहे थे विडियो
अनाप शनाप की।

जिस मॉडल ने तुम पर पोर्नग्राफी का आरोप लगाया उसका नाम गहना वशिष्ठ है और ऐसा लगता है कि यह गहना वशिष्ठ तुम्हारे घर के सभी गहने बिकवाकर ही दम लेगी। समझ नही आता तुम यह बात कैसे भूल गए कि जिस देश की सत्ता पर ऐसे लोग काबिज़ हैं जो यह कहते हैं कि न खाऊँगा न खाने दूंगा तो तुमको यह अनुमान तो लगा लेना चाहिए कि यह लोग न तो ऐसी विडियो न देखते हैं और न देखने देंगे और शायद इसीलिए भारत में बहुत सी स्पेशल बेवसाइट्स सालों पहले ही बैन कर दी गई थीं।

यदि तुमको लगता है कि कोई धंधा बुरा नही होता तो तुम सन्नी लियोनी को अपना आदर्श मानते और आराम से कनाडा चले जाते जहां से वह आई थी।फिल्मों के कारण कम तथा योग के कारण ज्यादा मीडिया में बनी रहने वाली शिल्पा शेट्ठी तुम्हारी करतूतो के कारण मीडिया से मुंह छिपाकर भाग रही है। कपालभाति करने वाली यह अभिनेत्री वकीलों और पुलिस के समक्ष अब शीर्षासन करती दिख रही हैं।

बहरहाल राज कुंद्रा को विडियो के शौकीन उन युवाओं की हाय लगी है जिनको राज कुंद्रा के डायरेक्शन में बनी इन नीली फिल्मों का लिंक अभी तक नही मिला है मौजूदा समय पर राज पुलिस कस्टडी पर है और वहीं से गीत गुनगुना रहा है बचपन का प्यार मेरा भूल नही जाना रे।

आशीष तिवारी निर्मल
www.womenexpress.in

एक नजर

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ा

मुंबई, 22 जुलाई । वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 400 अंक से अधिक चढ़ा।

इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 444.17 अंक या 0.85 प्रतिशत बढ़कर 52,642.68 पर कारोबार कर रहा था, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 129.15 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 15,761.25 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक तीन प्रतिशत की तेजी बजाज फाइनेंस में हुई। इसके अलावा टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस भी बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे।

सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर

मतभेदों को दूर करने के लिए नवजोत सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र

(विशेष संवाददाता)

चंडीगढ़, 22 जुलाई । पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिह शुक्रवार को उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां नवजोत सिह सिद्धू औपचारिक रूप से प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कार्यक्रम में उनके जाने की पुष्टि की।

मुख्यमंत्री के साथ अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास करते हुए सिद्धू ने भी एक पत्र लिखकर अमरिंदर सिह से कार्यक्रम में आने का आग्रह किया और कहा कि उनका ''कोई निजी एजेंडा नहीं है।'' सिद्धू ने कहा, ''पंजाब के मुद्दों पर मेरे संकल्प और प्रतिबद्धता तथा प्रत्येक पंजाबी के कल्याण के लिए आलाकमान के जनहितैषी 18 सूत्री एजेंडे को पूरा करने से आप और सभी परिचित हैं। सिद्धू ने लिखा, ''हमारे पंजाब कांग्रेस परिवार में सबसे बड़े होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आएं और नयी टीम को अपना आशीर्वाद दें। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के ट्वीट के पहले, पार्टी की प्रदेश इकाई के नवनियुक्त चार कार्यकारी अध्यक्षों में से कुलजीत सिह नागरा और संगत सिह गिलजियान ने मुख्यमंत्री को पदभार संभालने के कार्यक्रम के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। निमंत्रण पत्र पर 55 से ज्यादा विधायकों ने हस्ताक्षर किए। पिछले कुछ समय से सिद्धू और अमरिंदर का टकराव चलता रहा है। अमृतसर (पूर्व) के विधायक सिद्धू ने पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामले

के लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध किया था और कहा था कि जब तक सिद्धू उनके खिलाफ अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगेंगे वह उनसे नहीं मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं ने बृहस्पतिवार को अमरिंदर सिह से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने एक ट्वीट में कहा, ''पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों को शुक्रवार को दिन में 10 बजे चाय के लिए पंजाब भवन आमंत्रित किया है। इसके बाद सभी साथ मिलकर नयी पीपीसीसी टीम के कार्यभार संभालने के कार्यक्रम के लिए पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे। नागरा ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आएंगे। नागरा ने कहा, ''मुख्यमंत्री को प्रधान साहब (पीपीसीसी अध्यक्ष), मंत्रियों और विधायकों की ओर से न्योता दिया गया है। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचेंगे।'' अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री अमरिदर सिह के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को सिद्धू को पार्टी की पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सिद्धू की सहायता के लिए संगत सिह गिलजियान, सुखविदर सिह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिह नागरा को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बुधवार को सिद्धू का समर्थन करने वाले कई विधायकों ने कहा था कि उन्हें अमरिदर सिह से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी मामले की जांच रिपोर्ट को खारिज करने के बाद इस साल अप्रैल में मुख्यमंत्री और सिद्धू के बीच तनाव बढ़ गया था। सिद्धू ने 2015 में बेअदबी और उसके बाद पुलिस की गोलीबारी की घटनाओं में न्याय में कथित देरी के मुद्दे पर अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। सिद्धू ने 2019 में स्थानीय निकाय विभाग वापस लिए जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़कर सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

कोविड की दूसरी लहर के बावजूद 2021 की पहली छमाही में विज्ञापन-समय में वृद्धि

(विशेष संवाददाता)

मुंबई, 22 जुलाई । कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के बावजूद, टेलीविजन पर विज्ञापनसमय एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत और 2019 में महामारी से पहले के समय की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ी है। बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि टीवी उद्योग ने जनवरीजून 2021 में 87.4 करोड़ सेकंड का विज्ञापन देखा, जबकि 2020 में इसी अवधि के लिए 63.8 करोड़ सेकंड और 2019 में 77.7 करोड़ सेकंड का विज्ञापन देखा। महामारी का सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था के साथसाथ वित्त वर्ष 2020-21 में भी संकुचन हुआ है। जून तिमाही में दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, और नीति निर्माताओं का कहना है कि अर्थव्यवस्था में मांग

प्रभावित हुई है तथा खपत कम है। काउंसिल के राजस्व विभाग के प्रमुख आदित्य फाटक ने कहा, '2021 की पहली छमाही के लिए विज्ञापनकी मात्रा (विज्ञापन दिखाने का समय) पूरे उद्योग के लिए आशाजनक और उत्साहवर्धक है। सक्रिय विज्ञापनदाताओं और ब्रांडों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। विज्ञापनदाताओं में रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान बनाने वाली कंपनियों का योगदान बराबर ऊंचा बना हुआ है। आलोय वर्ष में कुल दिखाए गए टीवी विज्ञानों में इस क्षेत्र का हिस्सा 40 प्रतिशत (56.6 करोड़ सेकेंड) रहा। ईवाणिज्य कंपनियों की ओर से भी विज्ञापन बढ रहा है। इस दौरान इनका योगदान 7.8 करोड़ सेकेंड रहा।

लगातार दूसरे दिन बढ़े सक्रिय मामले, सरकार ने कहा- राज्यों के पास वैक्सीन की 3.20 करोड़ डोज उपलब्ध

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास फिलहाल वैक्सीन की 3.20 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ डोज से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं और सात लाख डोज देने की प्रक्रिया चल रही है।

सरकार टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच लगातार दूसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 41,383 मामले सामने आए हैं जिसके चलते कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,12,57,720 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को सक्रिय मामलों की संख्या 4,09,394 हो गई। इससे एक दिन पहले बुधवार को सक्रिय मामलों की संख्या 4,07,170 थी। इस तरह गुरुवार को सक्रिय मामलों की संख्या में 2,224 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले बुधवार को सक्रिय मामलों में एक हजार से अधिक की वृद्धि हुई थी। मंत्रालय के अनुसार, इस बीमारी से देश में अब तक 3,04,29,339 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ, कोरोना से मौत को कम बताने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए सरकार ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हर मौत का कारण कोरोना को मान लिया गया है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है और पूरी तरह गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में मजबूत और कानून आधारित मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रणाली है। इसे देखते हुए कुछ मामले संक्रामक रोग और उसके प्रबंधन के नियमों के अनुसार ज्ञात नहीं हो सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में इसका पता नहीं चलने की संभावना नहीं है।

ब्लैकबक ने 67 मिलियन डॉलर जुटाए भारत से यूनिकॉर्न क्लब में किया प्रवेश

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

बेंगलुरू, 22 जुलाई। ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ब्लैकबक ने घोषणा की है कि उसने ट्राइब कैपिटल, आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड और वीईएफ के नेतृत्व में 67 मिलियन डॉलर के इक्विटी वित्तपोषण को बंद कर दिया है। इसका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर हो गया है, इसके साथ ही यह देश का एक और यूनिकॉर्न बन गया है।

ब्लैकबक के पास अपने प्लेटफॉर्म पर 700,000 से अधिक ट्रक और 1.2 मिलियन से अधिक ट्रक हैं। सालना लेनदेन में 15 मिलियन से अधिक और वर्तमान में सभी ऑनलाइन ट्रकिंग गतिविधियों के 90 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी चला रहे हैं। ब्लैकबक के सहसंस्थापक और सीईओ राजेश याबाजी ने कहा, ब्लैकबक ने ट्रकिंग की फिर से कल्पना करने के सपने के साथ शुरूआत की, इसे 10एक्स सरल और 10एक्स कुशल बनाने के लिए। छह साल हो गए हैं और हम अभी शुरूआत कर रहे हैं। मौजूदा निवेशकों वेलिंगटन मैनेजमेंट, सैंड्स कैपिटल और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भी दौर में भाग लिया। कंपनी के पास एसएमई और हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, कोका कोला, एशियन पेंट्स, टाटा, वेदांत, एलएंडटी और जिंदल जैसे बड़े कॉरपोरेट सहित 10,000 से अधिक ग्राहक हैं।

ट्राइब के सहसंस्थापक और पार्टनर अर्जुन सेठी ने कहा, भारत की आपूर्ति श्रृंखला और रसद उद्योग कागज और पेंसिल से डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि को मापने की ब्लैकबक की क्षमता ने उद्योग के लिए कम समयसीमा में लॉजिस्टिक चुनौतियों को सुव्यवस्थित किया है। कंपनी इन फंडों का उपयोग बाजार में और आगे बढ़ने और अपने ग्राहकों के लिए नई सेवा पेशकशों को लॉन्च करने के लिए करेगी।

अलीगढ़ में मानसून ने सड़क निर्माण पर लगाए ब्रेक, कई टेंडर अटके

अलीगढ़, 22 जुलाई। मानसून ने सड़क निर्माण पर ब्रेक लगा दिए हैं। निर्माण कार्य के कई टेंडर अटक गए हैं। जिन सड़कों का निर्माण हो रहा था, वह काम भी बंद है। बारिश में ये सड़कें और भी बदहाल हो गई हैं। इसको लेकर शहरवासी नगर निगम की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि मानसून से ऐन पहले सड़क निर्माण का काम क्यों छेड़ा गया। तीन महीने पहले भी काम शुरू हो सकता था। विभागीय अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। नगर निगम करीब 44 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च कर रहा है। कुछ सड़कों का निर्माण कार्य पिछले महीने ही शुरू हुआ है। सासनीगेट इलाके में प्रेम चैक से होली तक नालियां बन चुकी हैं। निर्माण सामग्री जगहजगह पड़ी है। अब बारिश में यहां पानी भर गया। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है। काम शुरू हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। बारिश के चलते अब काम रुक चुका है। क्षेत्रीय लोगों को आनेजाने में खासा दिक्कत हो रही है।

ग्राम पैतोरा में बिधायक के निर्देश पर इंटर लॉकिंग सड़क की नाप करवाते समाज सेवी ए बी शुक्ल

बहराइच । पयागपुर पिछले सप्ताह पैतोरा गांव के ग्रामीणों के बुलावे पर बिधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी ने समाज सेवी ए बी शुक्ला जे साथ गांव में पहुंचकर चौपाल लगायी थी। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शामिल थी। बिधायक प्रतिनिधि के सामने ग्राम वासियो ने पी एम शहरी आवास योजना में बड़ी संख्या में पात्रों के छूटने और आये आवासों में आ रही दिक्कतों की बात बतायी थी।साथ ही साथ गांव की कई गलियों में इंटर लॉकिंग मार्ग की मांग की थी।बिधायक प्रतिनिधि ने आवास से समन्धित समस्याओं के लिए तत्काल डूंडा के अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी थी और इंटर लॉकिंग मार्ग के लिए नगर पंचायत में प्रार्थना पत्र पहुंचाने के लिए कहा था।इसी क्रम में गुरुवार को बिधायक के निर्देश पर समाज सेवी ए बी शुक्ल और शानू शर्मा ने गांव की गलियों की नाप करवाकर प्रस्ताव नगर पंचायत और विधायक त्रिपाठी तक पहुचाया। नाप कार्य के समय हरी शंकर रावत, हवल दार शर्मा, मुनिजर चौहान विकी भोलू और रंजीत चौहान सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।ग्रामीणों ने बिधायक त्रिपाठी को ग्रामीणों की समस्या पर तत्काल ध्यान देने के लिए प्रसंशा की और धन्यबाद भी ज्ञापित किया है ।

पेगासस परियोजना पर चर्चा के लिए मनीष तिवारी ने दिया स्थगन नोटिस

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 22 जुलाई। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को पेगासस परियोजना पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। तिवारी ने तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कामकाज को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया, कि रिपोटरें में बताया गया है कि सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ समूह द्वारा विकसित निगरानी उपकरण पेगासस की खरीद की है जो पत्रकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निगरानी के लिए है।

अपने नोटिस में तिवारी ने कहा कि चूंकि एनएसओ समूह की नीति यह है कि ग्राहक केवल जांच की गई सरकारों तक ही सीमित हैं, इससे पता चलता है कि स्पाइवेयर का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया गया था, न कि किसी अन्य निजी निकाय द्वारा।

उन्होंने कहा, सिटिजन लैब जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों ने कुछ उपकरणों पर स्पाइवेयर के निशान पाए हैं जिन पर हमला किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की निगरानी को हैकिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि एक स्पाइवेयर करता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार अनधिकृत अवरोधन या हैकिंग बहुत योग्य होता है । उन्होंने आगे कहा कि तथ्य यह है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार नहीं किया है कि आधिकारिक तौर पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। तिवारी ने कहा, सर, यह गंभीर चिंता का विषय है और इसलिए मैं इसे उठाना चाहता हूं।

इस मुद्दे ने मानसून सत्र के लिए एक तूफानी शुरूआत शुरू कर दी, जब एक वैश्विक सहयोगी जांच परियोजना से पता चला कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप्स के पेगासस स्पाइवेयर को भारत में 300 से अधिक मोबाइल फोन नंबरों को लक्षित किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के दो मंत्री, तीन विपक्षी नेता, संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यवसायी भी शामिल थे।

न्यायालय ने मध्य प्रदेश बसपा विधायक के पति की हत्या मामले में जमानत रद्द की

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेबवार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चैरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश की बसपा विधायक के पति जमानत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को न्याय के प्रशासन से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने निष्पक्ष आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों में दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जमानत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इसमें कानूनी सिद्धांतों का सही इस्तेमाल नहीं किया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने में गंभीर गलती की है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आशंका की एक महीने के भीतर जांच की जाए। न्यायाधीश ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा था कि दमोह पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा उन पर ष्दबावष् डाला गया था। फरार चल रहे सिंह को 28 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जब शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को उसे गिरफ्तार करने या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने की एक समयसीमा दी थी। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च को कहा था कि आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया क्योंकि डीजीपी ने कहा था कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार या पकड़ नहीं पायी थी। शीर्ष अदालत ने चैरसिया के बेटे सोमेश और राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया। इन अपील में सिंह की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था। दलीलों में दावा किया गया कि वह जमानत पर रहते हुए कई हत्या के मामलों में शामिल था। चैरसिया की मार्च 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद हत्या कर दी गई थी।

मृत्यु पंजीकरण की मजबूत व्यवस्था, कोविड से हुई मौत का पता न चलने की गुंजाइश नहीं: सरकार

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 22 जुलाई। सरकार ने बृहस्पतिवार को उन खबरों का खंडन किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत में कोविड19 से मरने वाले लोगों की ''गणना काफी कम'' की गयी है और उसने कहा कि खबरों में यह माना गया है कि सभी अतिरिक्त मौतें कोविड19 की वजह से हुई जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और पूरी तरह गलत है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में मजबूत और कानून पर आधारित मौत पंजीकरण व्यवस्था को देखते हुए संक्रामक रोग और उसके प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों का पता न चले लेकिन मौतों का पता न चलने की गुंजाइश नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हाल में मीडिया में कुछ खबरें आयीं जिनमें आरोप लगाया गया कि भारत में महामारी के दौरान अतिरिक्त मौतों की संख्या लाखों में हो सकती है और इसमें कोविड19 की आधिकारिक मृतक संख्या को ''बहुत कम'' बताया गया। इन खबरों में हाल के कुछ अध्ययनों का हवाला देते हुए ''भारत में सीरो संक्रमण दर के आधार पर अतिरिक्त मौतों की गणना करने के लिए अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के उम्र संबंधी संक्रमण दरों का इस्तेमाल किया गया है।'' बयान में कहा गया है, ''खबरों में यह माना गया है कि सभी अतिरिक्त मौतें कोविड19 से हुई मौतें हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं है और पूरी तरह गलत है। अतिरिक्त मृत्यु ऐसा शब्द है जो सभी वजहों से होने वाली मौतों के आंकड़ें को बताता है और इन मौतों को कोरोना वायरस की वजह से बताना पूरी तरह गुमराह करना है।'' सरकार ने कहा कि भारत की संक्रमण का पता लगाने की व्यापक रणनीति है। इसके अलावा देश में 2,700 से अधिक जांच प्रयोगशालाएं हैं जहां कोई भी जांच करा सकता है।

इसके साथ ही लक्षणों और चिकित्सा देखभाल के बारे में जागरूकता अभियान चलाए गए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लोग जरूरत के वक्त अस्पतालों तक पहुंच सकें। भारत में मजबूत और कानून पर आधारित मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था होने के कारण मौतों का पता न चलने की संभावना नहीं है।

उसने कहा कि मृत्यु दर के मामले में यह देखा जा सकता है जो 31 दिसंबर 2020 को 1.45 प्रतिशत थी और अप्रैलमई 2021 में दूसरी लहर में संक्रमण के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के बाद भी मृत्यु दर आज 1.34 प्रतिशत है।

भारत में गरीब और अमीर के लिए दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकतीं: न्यायालय

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों और न्याय तक पहुंच एवं संसाधनों से वंचित ''छोटे लोगों'' के लिए दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि ''जिला न्यायापालिका से औपनिवेशिक सोच'' के साथ किए जा रहे व्यवहार को नागरिकों के विश्वास को बचाए रखने के लिए बदलना होगा और जब न्यायाधीश ''सही के लिए खड़े होते हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जाता है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश की बसपा (बहुजन समाज पार्टी) विधायक के पति को दी गई जमानत बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए ये अहम टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है और इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा, ''भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और

राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों और न्याय तक पहुंच एवं संसाधनों से वंचित ''छोटे लोगों'' के लिए दो अलगअलग समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती।

शीर्ष अदालत ने कहा, ''दोहरी व्यवस्था की मौजूदगी कानून की वैधता को ही खत्म कर देगी। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध होने का कर्तव्य सरकारी तंत्र का भी है। पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका नागरिकों के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। पीठ ने कहा, ''अगर न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास कायम रखना है तो जिला न्यायपालिका पर ध्यान देना होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालतों के न्यायाधीश भयावह परिस्थितियों, बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा के बीच काम करते हैं और न्यायाधीशों को सही के लिए खड़े होने पर निशाना बनाए जाने के कई उदाहरण हैं। पीठ ने कहा कि दुख की बात है कि स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए उच्च न्यायालयों के प्रशासन की अधीनता भी उन्हें कमजोर बनाती है। पीठ ने कहा, ''जिला न्यायपालिका से साथ औपनिवेशिक मानसिकता वाला व्यवहार बदलना चाहिए और ऐसा होने पर ही प्रत्येक नागरिक, भले वह आरोपी हो, पीड़ित हो या नागरिक समाज का सदस्य है, उसकी नागरिक स्वतंत्रत हमारी निचली अदालतों में सार्थक रूप से संरक्षित रहेगी। ये निचली अदालतें उन लोगों की रक्षा की पहली ढाल हैं, जिनके साथ गलत हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक स्वतंत्र संस्था के रूप में न्यायपालिका का कार्य शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा में निहित है। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश किसी भी अन्य कारकों की बाधा के बिना कानून के अनुसार विवादों को सुलझाने में सक्षम होने चाहिए और इसके लिए न्यायपालिका और प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता जरूरी है न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में यह भी शामिल है कि वे अपने वरिष्ठों और सहयोगियों से स्वतंत्र हों।

नैनी (प्रयागराज) कार्यालय
नैनी स्टेशन के सामने
प्रभारी:
सुजीत चौरसिया
Mo- 9451251066

वूमेन एक्सप्रेस
स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुनील पाण्डेय ने आदित्य ग्राफिक्स INC, प्रताप भवन, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1 से मुद्रित व ई–4/168, गली नंबर–6, सागर मार्केट, साढे 4 पुस्ता, सोनिया विहार दिल्ली–94 से प्रकाशित किया।
RNI.DELHIN / 2013/ 48606
मो.– 07042999974
टेली– 09013 518 518
www.womenexpress.in
thewomenexpress@gmail.com

वूमेन एक्सप्रेस

दैनिक भास्कर, भारत समाचार चैनल के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी

एक नजर

फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ने वन संरक्षण के लिए कैनोपी के साथ समझौता किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई। ई कॉमर्स क्षेत्र के फ्लिपकार्ट समूह और फैशन इंटेलर मिंत्रा ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग और अन्य सामग्री लेने के लिए गैरलाभकारी संगठन कैनोपी के साथ साझेदारी की है। एक बयान में कहा गया कि कैनोपी के पैक4गुड (पैकेजिंग) और कैनोपी स्टाइल (फैशन) पहल के तहत फ्लिपकार्ट समूह की दो कंपनियां वन आधारित उत्पादों की जगह वैकल्पिक साधनों को अपनाएंगे और इसके तहत कच्चे माल के लिए जंगलों पर निर्भरता कम की जाएगी। बयान के मुताबिक, ''फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जलवायु स्थिरता कायम रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा में दुनिया के जंगलों की भूमिका को पहचानते हैं।'' फ्लिपकार्ट और मिंत्रा अगले तीन वर्षों में नालीदार कागज और पेपरबोर्ड के इस्तेमाल को कम करेंगे और इसकी जगह दोबारा इस्तेमाल के योग्य शिपिंग बॉक्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइनः ऊर्जा मंत्री

लखनऊ, 22 जुलाई। उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं अगले महीने से ऑनलाइन हो जाएंगी। इससे उपभोक्ताओं को मीटर बदलवाने और बिल ठीक कराने समेत विभिन्न कार्यों के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बृहस्पतिवार को विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को विद्युत उपकेंद्र का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए ऊर्जा विभाग के ऐप और पोर्टल पर अगले माह से मीटर बदलने, बिल सही कराने, लोड परिवर्तन, नाम व पते में सुधार, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन और कनेक्शन को स्थाई रूप से कटवाने के आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे। इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत होगी। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं को गलत बिल मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शनों में भी गलत बिल आने की शिकायतें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। शर्मा ने कहा कि इस बार गर्मियों में 25 हजार मेगावाट से ज्यादा की मांग की आपूर्ति की जा रही है। अगले साल यह मांग बढ़कर 28 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है।पारेषण नेटवर्क के साथ ही वितरण नेटवर्क भी उसी अनुरूप बेहतर हो।

आगरा में सामूहिक हत्याकांड से सनसनी, तीन बच्चों और मां की गला रेतकर हत्या

आगरा, 22 जुलाई। आगरा के कोतवाली इलाके में घनी आबादी के बीच कूचा साधूराम में महिला और उसके तीन बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह सामूहिक हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। घर की अलमारियां खुली मिलने से लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जताई गई है। पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस महिला के पति से पूछताछ कर रही है। कोतवाली में घनी आबादी वाली बस्ती कूचा साधूराम निवासी 36 वर्षीय रेखा राठौर का दो साल पहले पति सुनील राठौर से तलाक हो गया था। पति माईथान में रहता है। जबकि रेखा अपने तीनों बच्चों टुकटुक (12 साल), पारस (10 साल) और माही (8 साल) के साथ यहां रहती थीं। गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे बस्ती के लोगों ने रेखा के घर का दरवाजा खुला देखा। रोज की तरह जब घर से बाहर कोई बच्चा खेलता नहीं दिखा तो गड़बड़ी की आशंका पर पड़ोस के लोग अंदर पहुंचे। वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए।

गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों की नई तारीखों का ऐलान, 22 अगस्त को होगी वोटिंग

दिल्ली सरकार ने अदालत को दी जानकारी, 25 अगस्त को होगी मतगणना

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली, 22 जुलाई । दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के आम चुनाव 22 अगस्त को हो सकते हैं। चुनाव कराने के लिए दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय तैयार हो गया है। निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर आगामी 22 अगस्त को चुनाव करवाने और 25 अगस्त को मतगणना करवाने की जानकारी दी है। इसके साथ ही अब गुरुद्वारा चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी।

इस बार दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव 46 वार्डों की बजाय 45 वार्डों पर ही होंगे। खुरैजी खास सीट पर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के प्रत्याशी का निधन हो गया है। जिसके चलते वार्ड का चुनाव गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने रदद कर दिया है। इस सीट के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया नामजदगी और बाकी सारी व्यवस्था नये सिरे से होगी, जबकि 45 वार्डों में कोई नामांकन नहीं होगा। इस संबंधी पुराने छप चुके बैलेट पेपर पर ही चुनाव करवाया जाएगा।

45 वार्डों के चुनावों के लिये अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होने की सम्भावना है। बता दें कि इससे पहले गुरुद्वारा कमेटी के आम चुनाव 25 अप्रैल को होने थे, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर मची हाहाकार और बढ़ते केसों के कारण दिल्ली सरकार ने 21 अप्रैल को चुनाव स्थगित कर दिए थे। चुनाव स्थगित होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशी शांत हो गए और नई तारीखों का इंतजार करने लगे।

अब सरकार की ओर से चुनाव कराने के मिले संकेत के बीच चुनाव प्रचार एक बार फिर तेजी पकडऩा शुरू कर दिया है। बता दें कि

गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में इस बार शिरोमणि अकाली दल (बादल), शिरोमणि अकाली दल (दिल्ली), जागो पार्टी, पंथक अकाली लहर, सिख सदभावना दल चुनाव मैदान में है। गुरुद्वारा कमेटी चुनाव के लिए करीब साढ़े 3 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो मतदान करेंगे। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल बादल ने कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जल्द से जल्द चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि जानबूझ कर चुनाव को लटकाया जा रहा है। अकाली दल ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। याचिका अकाली दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने दायर की थी।

इस मामले में आज चीफ जस्टिस डी.एन पटेल व जस्टिस ज्योति सिंह की बैंच के समक्ष सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जब अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा जवाब मांगा तो फिर सरकार ने जवाब दिया कि चुनाव 22 अगस्त को करवाने के लिए तैयार हैं और इनका परिणाम 25 अगस्त को घोषित किया जाएगा।

उधर, शिरोमणी अकाली दल (दिल्ली) के महासचिव हरविंदर ड्क्षसह सरना ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि वह बहुत खुश हैं। जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए, यह सभी दलों के लिए ठीक है। उन्होंने कहा कि चुनाव होने के साथ ही बड़े बदलाव आएंगे।

4 साल होता है गुरुद्वारा कमेटी का कार्यकाल

दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के चुनाव, दिल्ली सरकार गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से करवाए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है। पिछला चुनाव फरवरी 2017 में करवाए गए थे। पूरी दिल्ली को चुनाव की दृष्टि से 46 गुरुद्वारा वार्डों में बांटा गया है। गुरुद्वारा वार्ड मतदाता सूची में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के पात्र सिक्ख नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है। अभी तक की गुरुद्वारा वार्ड मतदाता सूची में 3,83561 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, हालांकि इसी में से फर्जी एवं बोगस वोटों को कैंसिल कर दिया गया है, जो निर्धारित स्थान पर नहीं रह रहे हैं। वर्ष 2017 में हुए गुरुद्वारा चुनाव में 45.68 प्रतिशत मतदान हुआ था। करीब साढ़े 3 लाख वोटर वर्तमान में हैं।

विरोधी दल रूकवाना चाहते थे चुनावः कालका

अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष हरमीत कालका ने कहा कि यह अकाली दल की बड़ी जीत है और विरोधियों द्वारा बारबार किये जा रहे झूठे दावे औंधे मुँह गिरे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से यही मांग कर रहे थे कि गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव तुरंत करवाये जाएं जबकि विरोधी आप व भाजपा सरकार के साथ मिल कर चुनाव लटकाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन चुनावों में उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।

अलाभकारी हवाई अड्डों के पीपीपी के तहत विकास की जरूरत को स्वीकारा

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । संसद की एक समिति ने यह स्वीकार किया है कि देश के छोटे एवं अलाभप्रद हवाई अड्डों की देखरेख और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की अपरिहार्य आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को पेश की गयी पर्यटन,परिवहन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। समिति ने भारतीय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 के बारे में अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। भाजपा नेता टी जी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कहा, ''समिति इस बात को मानती है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए देश में सभी हवाई अड्डों के विकास और रखरखाव के लिए अपेक्षित निवेश की पूर्ति करना संभव नहीं है। समिति छोटे और अलाभकारी विमानपत्तनों के विकास और रखरखाव में सार्वजनिक निजी भागीदारी की अपरिहार्य आवश्यकता

को समझती है। समिति ने इस विधेयक में ''महा विमानपत्तन'' की जो परिभाषा प्रस्तावित की गयी है, उसको भी स्वीकार करते हुए कहा है कि इससे छोटे एवं अलाभकारी हवाई अड्डों के विकास एवं रखरखाव में मदद मिलेगी। विधेयक में महा विमानपत्तन की परिभाषा में हवाई अड्डों के समूह को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ते हुए हवाई यातायात का कुशलतापूर्व प्रबंधन किए जाने के लिए आवश्यक है कि हवाई अड्डा आधारभूत ढांचे की सतत निवेश आवश्यकता को पूरा किया जाए। समिति ने कहा कि विधेयक में इस ओर ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने भारतीय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया है।

संपत्ति विवाद में राजमाता को जान से मारने की धमकी देने के लिए पन्ना राजघराने की बहू गिरफ्तार

(विशेष संवाददाता)

पन्ना (मध्यप्रदेश), 22 जुलाई । मध्यप्रदेश के पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी देवी को अपनी सास राजमाता दिलहर कुमारी को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने के मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये जाने के बाद जीतेश्वरी देवी को यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमलेश कुमार सोनी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि जीतेश्वरी देवी (करीब 50 साल) के खिलाफ यह कार्रवाई उनकी सास राजमाता दिलहर कुमारी (करीब 75 साल) की शिकायत पर की गई है। पन्ना कोतवाली थाने के पुलिस निरीक्षक अरुण सोनी ने बताया कि कोतवाली में राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पर महारानी जीतेश्वरी देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (जान से मारने की धमकी), 147 (बलवा करना), 148 (हथियारों के साथ बलवा करना), 149 (समूह

द्वारा हिंसा), 294 (अश्लील कार्य), 323 (जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाना), 427 (ऐसी कोई कुचेष्टा करेगा और जिससे पचास रुपए या उससे अधिक की हानि या नुकसान हो), 458 (क्षति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के करके रात में गृहअतिचार) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत बृहस्पतिवार सुबह यहां गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि राजमाता द्वारा 19 जून को दिए एक शिकायती पत्र पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि इसमें राजमाता ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने 19 जून की रात महारानी जीतेश्वरी देवी ने अपने पक्ष के कुछ लोगों के साथ महल में मेरे पक्ष के कुछ लोगों पर हमला करने के साथसाथ गालीगलौच एवं मारपीट की। राजमाता ने यह भी कहा है कि महारानी ने अपने लोगों के साथ मेरे पक्ष के लोगों को कट्टा दिखाकर धमकी भी दी थी। सोनी ने बताया कि सासबहू की लड़ाई संपत्ति विवाद को लेकर लंबे समय से चली आ रही है और इस मामले में हमारे थाने में राजमाता की शिकायत पर 597/21 के तहत प्रकरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक ही महल में रहते हैं। सोनी ने बताया कि राजमाता की शिकायत पर पुलिस ने महारानी सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से एक को दो दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चार फरार हैं। सूत्रों के अनुसार इस राजघराने में विशेष रूप से राजमाता दिलहर कुमारी एवं उनकी बहू जीतेश्वरी देवी के बीच करोड़ों रुपये की संपत्ति एवं हीरों को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। इस बीच, गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाहन में बैठते समय जीतेश्वरी देवी ने मीडिया से कहा, ''मैं निर्दोष हूं। झूठी शिकायत पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। बदले की भावना से यह शिकायत की गई है।''

राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे सभी स्कूल

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मंद पड़ने और आईसीएमआर की ओर से स्कूलों को खोले जाने की वकालत के बाद राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने 2 अगस्त से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है तो गुजरात में 26 जुलाई से 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थी क्लास में बैठ सकेंगे। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे तो 5 से 8वीं तक के विद्यार्थी भी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जा सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 2 अगस्त से खोलने पर सहमती बनी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 2 अगस्त से खोलने का फैसला लिया है। कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। कोचिंग और कॉलेज खोलने की तारीख बाद में तय होगी। कोराना की दूसरी लहर के बाद से मार्च से ही स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं शुरू करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

आईबीएम बेंगलुरु हवाई अड्डे के संचालन का डिजिटलीकरण करेगा

(विशेष संवाददाता)

बेंगलुरु, 22 जुलाई । बुधवार को इसके ऑपरेटर ने कहा कि वैश्विक सॉफ्टवेयर प्रमुख आईबीएम उड़ान भरने वालों के अनुभव को बदलने के लिए बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन को डिजिटल करेगा। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल), एक सार्वजनिकनिजी संघ, जो देश का तीसरा सबसे बड़े हवाई अड्डे का संचालन करता है, ने एक बयान में कहा कि हमने केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे के संचालन के लिए अपने आईटी नेटवर्क को डिजिटाइज करने के लिए आईबीएम की वैश्विक व्यापार सेवा शाखा के साथ 10 साल की साझेदारी में प्रवेश किया है। रेड हैट ऑटोमेशन और आईबीएम के प्रबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस की एक इकाई,

किंड्रील, यात्रियों के यात्रा अनुभव को बदलने के लिए बॉक्स प्लेटफॉर्म में एक हवाई अड्डा बनाने के लिए यूएस आधारित आईटी दिग्गज के साथ साझेदारी करेगी। ऑपरेटर ने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ते हवाई अड्डों में से एक के रूप में, हमें परिचालन लचीलेपन के साथ, भविष्य में यात्री यातायात में वृद्धि को संभालने के लिए एक फुतीर्ली, स्केलेबल और लागतप्रतिस्पर्धी तकनीक की आवश्यकता है। नए प्लेटफॉर्म से ऑपरेटर की कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, इसकी आईटी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, इन्वेंट्री नियंत्रण और बेहतर घटना प्रबंधन के माध्यम से लागत कम होने की उम्मीद है। बीआईएएल ने बयान में कहा कि आईबीएम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के व्यवसाय के विकास का समर्थन करेगा और आईबीएम मैक्सिमो एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से संचालित अंतर्दृष्टि उत्पन्न करेगा।

युवाओं को धमकायें नहीं योगी, उनकी प्रापर्टी भी हो सकती है जब्तः प्रियंका

लखनऊ, 22 जुलाई । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर युवाओं को डराने धमकाने का आरोप लगाते हुये कहा कि जायज मांगों के लिये आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। मुख्यमंत्री के बुधवार को एक कार्यक्रम में युवाओं से किसी के बहकावे में न आने की अपील पर कटाक्ष करते हुये वाड्रा ने गुरूवार को ट्वीट किया, इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी माँगो के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज माँगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है।

उन्होने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं, वह उनकी नहीं देश की जनता की है.. याद रखें कि वह प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में 130 नव नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के मौके पर कहा था कि सरकार की पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली के कारण सरकारी विभागों में चयन की प्रक्रिया अब समय से पूर्ण हो रही है। युवाओं को किसी बहकावे में नहीं आना चाहिये। आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपनी प्रापर्टी जब्त करानी हो, वह गलत कार्य करे।

हिमाचल कैबिनेटः 26 जुलाई से कोचिंग, 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल

10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हुए स्कूल खोलने को अनुमति दी गई

(विशेष संवाददाता)

शिमला । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हुए स्कूल खोलने को अनुमति प्रदान की गई।

इन कक्षाओं के लिए आवासीय और आंशिक आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कुल्लू के निरमण्ड और जिला शिमला के कोटखाई एवं जुब्बल में तीन उपमण्डल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के विकास खण्ड पांवटा साहिब के पुनर्गठन से तिरलोधार में नया विकास खण्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। मंडी जिला के सुन्दरनगर व बल्ह विकास खण्डों के पुनर्गठन से धनोटू के शेगली में नया विकास खण्ड बनाने

का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती द्वारा जे.ओ.ए. (आईटी) के 100 पद भरने का निर्णय लिया। शिमला जिला के कोटखाई स्थित कलबोग में नई उपतहसील और जुब्बलकोटखाई के टिक्कर में अग्निशमन केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में मैसर्ज प्रीमियर अल्कोबेव प्राईवेट लिमिटिड कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में 250 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल में मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर में 4.28 करोड़ रुपये की लागत से सीटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के भराड़ी में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सह शैक्षणिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सर्वेयर तथा ऑफिस असिस्टेंट सहकंपयूटर ऑपरेटर के दो ट्रेड्स को सीटों सहित मोटर वाहन मैकेनिक एवं फिटर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। यह संस्थान निजी भवन में चल रहा है इसलिए परिवर्तित किए गए ट्रेड्स को संस्थान को अपने भवन में स्थानांतरित करने के पश्चात् आरम्भ किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़जमूला के सुचारू संचालन के लिए तीन अतिरिक्त पद भरने की मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालकों के तीन पदों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का निर्णय लिया। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में चैकीदार के 5 पद दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ का नाम बदलकर शहीद सुबेदार संजीव कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ रखने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। शहीद सुबेदार संजीव कुमार को उनकी वीरता एवं साहस के लिए मरणोपरांत शहीद सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राज्य में कोविड19 की स्थिति, कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम, यूजीसी के दिशानिर्देशों व शिक्षा संस्थानों को खोलने पर भी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।